RNI NO.- CHHHIN/2023/87391

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

अंक-03 | वर्ष-3 | माह-जून 2025 | प्रकाशन तिथि- जून 2025 | रायपुर से प्रकाशित | पृष्ठ-40 | मूल्य-11/-

मोदी सरकार 3.0 का एक वर्ष

परिवर्तन, प्रगति और प्रतिबद्धता का प्रतीक

अबूझमाड़ में सुशासन की नई बयार

समाधान शिविरों से समस्याओं का समाधान

ग्रामीणों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ..

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम
की संयुक्त विशेष भर्ती योजना

"बीमा सखी" महिला बीमा अभिकर्ता

3 वर्ष तक प्रतिमाह मानदेय

- 1st Year Rs. 7000 P.M.
- 2nd Year Rs. 6000 P.M.
- 3rd Year Rs. 5000 P.M.

साथ ही आकर्षक अतिरिक्त कमीशन

बीमा सखी के अन्य लाभ

पार्ट टाईम/फूल टाइम कार्य
ग्रुप बीमा, होम लोन इत्यादि

आवश्यक शर्तें : 10 वीं पास उम्र 18 वर्ष से अधिक

एलआईसी महिला विशेष भर्ती

महिला कैरियर एजेंट के रूप में
एलआईसी से जुड़ें

Years	RS
1st	Rs. 7000/-
2nd	Rs. 6000/-
3rd	Rs. 5000/-

B.V.S.Rajkumar
{OVER FOUR DECADES OF EXPERIENCE}
L.I.C.OF INDIA, RAIPUR

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

98266-38002

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

रविश बेंजामिन

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी

(विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 3

अबूझमाड़ में सुशासन की नई बयार

Pg 7

दुकान आवंटन में उपभोक्त ाओं के अधिकार और डेवलपर्स की जिम्मेदारियाँ- एक कानूनी विश्लेषण...

Pg 11

मोदी सरकार 3.0 का एक वर्ष, परिवर्तन, प्रगति और प्रतिबद्धता का प्रतीक

Pg 16

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी

Pg 20

हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार- मुख्यमंत्री साय

क्या इंसाफ अब पहचान और प्रसिद्धि देखकर किया जाएगा?

लोकतंत्र की बुनियाद न्याय और समानता पर टिकी होती है। जब यह बुनियाद हिलने लगती है और न्याय का पलड़ा व्यक्ति की पहचान, प्रभाव या लोकप्रियता के आधार पर झुकने लगे, तब सवाल उठता है कि क्या हम सचमुच एक समान कानून वाले राष्ट्र में जी रहे हैं? हाल ही की दो घटनाएं इस असमानता को उजागर करती हैं — एक तरफ फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन और दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से जुड़ी घटनाएं। कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन की फिल्म के प्रचार के दौरान भारी भीड़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिनेता को हिरासत में लिया और आयोजकों पर भी सख्ती दिखाई। यह कार्रवाई दिखाती है कि सरकार भीड़ से हुई एक मौत को गंभीरता से लेती है — और लेनी भी चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब ठीक इसके कुछ दिन बाद विराट कोहली के मैच में जीत के जश्न में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो जाती है, और सरकार पूरी तरह चुप्पी साध लेती है। क्या इसलिए कि विराट कोहली देश के सबसे बड़े खेल सितारों में से एक हैं? क्या न्याय अब इस बात पर निर्भर करेगा कि मौत किसके आयोजन में हुई? एक मौत पर सख्त कार्रवाई और 11 मौतों पर मौन– यह स्थिति लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए खतरनाक संकेत है। यहां कोई यह नहीं कह रहा कि विराट कोहली की नीयत पर संदेह किया जाए, लेकिन जिस तरह अल्लू अर्जुन से सवाल पूछे गए, उसी तरह क्रिकेट आयोजन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब आयोजन में भीड़ का नियंत्रण खो जाए, और जान चली जाए, तो लोकप्रियता एक ढाल नहीं बन सकती। सरकार की यह चुप्पी केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि न्याय की असमानता की मिसाल बनती जा रही है। इससे जनता में यह संदेश जाता है कि प्रभावशाली लोगों के लिए कानून अलग है और आम नागरिकों के लिए अलग। जरूरत है कि सरकार समानता के सिद्धांत पर खरे उतरते हुए हर ऐसी घटना में निष्पक्ष और सख्त कदम उठाए। चाहे वह आयोजन किसी फिल्म स्टार का हो या खिलाड़ी का — जब जान जाती है, तो हर मौत बराबर होनी चाहिए। यदि आज हम इस दोहरे मापदंड पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो कल न्याय केवल प्रभावशाली लोगों की बपौती बनकर रह जाएगा। और तब लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचेगा, उसकी आत्मा मर चुकी होगी।

(यह लेख समाज में न्याय, समानता और सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर एक विमर्श प्रस्तुत करता है। यदि आपके विचार अलग हों, तो हमें लिख भेजिए। लोकतंत्र में बहस और विचार सबसे बड़ा हथियार हैं।)

आपका अपना
भूषण राव

अबूझमाड़ में सुशासन की नई बयार

समाधान शिविरों से समस्याओं का समाधान, अबूझमाड़ में समाधान शिविर, ग्रामीणों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ...

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आदिवासी बहुल आबादी के लिए जाना जाता है। वर्षों तक यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन अब शासन की योजनाएं इस दुर्गम अंचल तक पहुँच रही हैं और लोगों की जमीनी समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हाल ही में नारायणपुर जिले के कोहकामेटा में आयोजित समाधान शिविर, जो सुशासन तिहार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है।

समाधान शिविर- प्रशासनिक सेवाओं का सशक्त माध्यम

नारायणपुर जिले के दूरस्थ वनांचल कोहकामेटा में आयोजित समाधान शिविर ने कई पंचायतों के ग्रामीणों को एक ही स्थान पर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया। इस शिविर में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवास सहायता राशि, व्हीलचेयर और पोषण किट जैसी सुविधाएं मौके पर ही प्रदान की गईं।

यह पहल उस सोच को दर्शाती है जिसमें शासन लोगों के दरवाजे तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है, बजाय इसके कि लोग महीनों कार्यालयों के चक्कर काटते रहें।

आठ क्लस्टरों में फैली पहल

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार, नारायणपुर ब्लॉक के आठ क्लस्टरों में समाधान शिविर आयोजित किए गए। शुक्रवार को आयोजित कोहकामेटा शिविर में पांगुड़, आदनार, मुरनार, गारपा, घमंडी, झारावाही, कंदाड़ी, कोंगे, कोहकामेटा, कच्चापाल, कुंदला, मेटानार और गोमे पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह विशाल सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीणों में शासन की योजनाओं को लेकर विश्वास बढ़ा है।

सुशासन तिहार- सरकार की सक्रियता का प्रतीक

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मण्डावी ने कहा, सरकार अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। यदि किसी को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, राशन या किसी अन्य समस्या का समाधान चाहिए, तो वह समाधान शिविर के माध्यम से आवेदन देकर समाधान प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में शिक्षा

और जागरूकता ही विकास की असली कुंजी है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को किसानों को समय पर धान और मक्का बीज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

विभागों की सहभागिता

- एकीकृत समाधान का प्रयास
- इस समाधान शिविर में विभिन्न विभागों ने सक्रिय भागीदारी निभाई
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई और अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- राजस्व विभाग ने मौके पर ही जाति, आय, निवास और जन्म प्रमाण पत्र जारी किए।
- पशुधन विकास विभाग ने पशुपोषण आहार किट वितरित की।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास, जनमन आवास, राशन कार्ड, डबरी मरम्मत, भूमि सुधार और आवास की प्रथम किस्त के चेक वितरित किए।
- समाज कल्याण विभाग ने वृद्धजनों को व्हीलचेयर और छड़ी प्रदान की।

सार्थक संवाद और समाधान

ओरछा ब्लॉक में यह शिविर तीन चरणों में आयोजित किया गया, जिसका अंतिम चरण कोहकामेटा में संपन्न हुआ। स्छरू अभयजीत मंडावी के अनुसार, शिविरों में जल जीवन मिशन, मनरेगा आदि से जुड़े आवेदन मिले, जिनका मौके पर निवारण किया गया।

प्रताप सिंह मंडावी ने बताया कि इस शिविर के जरिए सभी विभागों के आवेदन प्राप्त हुए और उनका समाधान किया गया। यह शिविर सिर्फ समस्या समाधान का मंच नहीं था, बल्कि ग्रामीणों को सरकार के साथ जोड़ने का एक सेतु भी था।

ग्रामीणों की संतुष्टि- जनभागीदारी की सफलता

सुंदर लाल कुमेटी, सरपंच कुंदला, ने बताया कि पंचायत की समस्याओं जैसे स्कूल मरम्मत, पानी की समस्या, नया भवन, सीसी रोड आदि के लिए आवेदन दिए गए और उनका समाधान भी किया

गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आंगनबाड़ी भवन और खेल मैदान के लिए भी मांग की गई है।

एक नई शुरुआत की ओर

समाधान शिविरों के माध्यम से अबूझमाड़ जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में न केवल शासन की योजनाएं सीधे जनता तक पहुँच रही हैं, बल्कि यह पहल लोगों की समस्याओं को एक ही स्थान पर सुलझाने का मंच बन गई है। इससे न केवल प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास का पुल बना है, बल्कि अबूझमाड़ के समग्र विकास की दिशा में यह एक सशक्त कदम भी सिद्ध हुआ है।

समाधान शिविर - सुशासन का सफल प्रयोग

अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, लेकिन समाधान शिविर जैसे नवाचारों से यह कार्य सरल, सुलभ और प्रभावी बनता जा रहा है। यह प्रयास न केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए है, बल्कि यह भविष्य के समावेशी और सतत विकास की नींव भी रखता है।

अबूझमाड़ में सुशासन तिहार की यह पहल एक उदाहरण है कि जब शासन, प्रशासन और जनभागीदारी एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिवर्तन असंभव नहीं, बल्कि निश्चित हो जाता है।

छत्तीसगढ़ में करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई

विकसित भारत के सपने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम...

भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के सपनों को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य एक नई और महत्वपूर्ण छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह परियोजना न केवल राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को देश के सबसे बड़े और तकनीकी रूप से उन्नत ट्रांसफॉर्मर निर्माण केंद्रों में शुमार कराएगी।

निवेश और परियोजना की महत्ता

इस नई निर्माण इकाई के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है, जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में न केवल पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ट्रांसफॉर्मर, जो ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ होते हैं, उनकी उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता देश के ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स की यह इकाई तकनीकी दृष्टि से अत्यंत उन्नत होगी, जो ऊर्जा क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई महत्वपूर्ण बैठक

इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री विवेक जैन ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में परियोजना की रूपरेखा, निवेश संभावनाओं और रोजगार सृजन के आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री जैन ने इस बात पर जोर दिया कि यह ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय ऊर्जा मांग को पूरा करेगी, बल्कि देश में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़, विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक मजबूत स्तंभ बने। यह निवेश केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। राज्य सरकार इस परियोजना को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन

यह परियोजना राज्य में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाएगी। आधुनिक ट्रांसफॉर्मर उत्पादन से न केवल छत्तीसगढ़ की बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि बिजली वितरण के दौरान होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। इससे ऊर्जा क्षेत्र अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनेगा।

साथ ही, इस इकाई के निर्माण और संचालन से राज्य के युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तकनीकी और गैर-

तकनीकी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षित और अर्ध-प्रशिक्षित युवा इससे लाभान्वित होंगे। यह कदम राज्य की युवा शक्ति को सशक्त बनाएगा और आर्थिक समृद्धि में योगदान देगा।

मेक इन छत्तीसगढ़ का सशक्त पहलू

इस परियोजना की सफलता से छत्तीसगढ़ का मेक इन छत्तीसगढ़ अभियान और मजबूत होगा। जहां राज्य ने अब तक कई क्षेत्रीय उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति की है, वहीं यह ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई एक नई तकनीकी क्रांति का प्रतीक बनेगी। स्थानीय रूप से विकसित उच्च तकनीक के उत्पाद पूरे भारत में ऊर्जा क्षेत्र को रोशन करेंगे।

यह पहल छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और राज्य की ब्रांडिंग को एक नई पहचान देगी। इससे आने वाले वर्षों में और भी निवेश आकर्षित होंगे, जो व्यापक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और सहयोग

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस परियोजना को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है। सरकारी तंत्र द्वारा निवेशकों को हर प्रकार की सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि परियोजना बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सके। यह न केवल उद्योग की वृद्धि में सहायक होगा, बल्कि राज्य के विकास लक्ष्यों को भी बल देगा।

करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रायपुर में स्थापित होने वाली ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उम्मीद और समृद्धि का द्वार खोलेगी। यह परियोजना न केवल आर्थिक विकास का नया अध्याय लिखेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करेगी। विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में यह कदम छत्तीसगढ़ को एक मजबूत और अग्रणी राज्य बनाने में सहायक होगा।

यह पहल स्पष्ट करती है कि जब राज्य सरकार और उद्योग मिलकर काम करते हैं, तो विकास की राह कितनी सुगम और सफल हो सकती है। छत्तीसगढ़ का यह औद्योगिक विकास मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

नकली खाद, बीज बेचने वालों और इसमें अधिकृत विक्रेताओं की संलिप्तता पर होगी कड़ी कार्रवाई - रामविचार नेताम

कृषि मंत्री ने खाद व बीज विक्रेताओं पर नजर रखने, स्टॉक के नियमित परीक्षण, गुणवत्ता की जांच तथा किसानों की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही के दिए निर्देश

नकली खाद, बीज की बिक्री पर अधिकृत विक्रेताओं पर एफआईआर के साथ लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रदेश में नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें अधिकृत विक्रेताओं की संलिप्तता पाए जाने पर एफआईआर के साथ ही लाइसेंस रद्द करने को कहा है। श्री नेताम ने विभागीय अधिकारियों को खाद व बीज विक्रेताओं पर नजर रखने, स्टॉक का नियमित परीक्षण करने, गुणवत्ता व मानकों की जांच करने तथा इस संबंध में किसानों की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में नकली (डुप्लीकेट) खाद की बिक्री और जमाखोरी की बढ़ती घटनाओं को सरकार गम्भीरता से ले रही है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी या अधिकृत विक्रेता नकली खाद, बीज की बिक्री में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोषियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगे और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। श्री नेताम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे खाद विक्रेताओं पर नियमित निगरानी रखें, खाद व बीज के स्टॉक का नियमित परीक्षण करें तथा खाद मानक के अनुरूप है या नहीं, इसकी भी जांच नियमित करें। उन्होंने किसानों से प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसानों से अपील की है कि वे खाद और बीज के अधिकृत विक्रय केन्द्रों से ही इन्हें खरीदें। किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी की सूचना तुरंत नजदीकी कृषि कार्यालय को दें।

दुकान आवंटन में उपभोक्ताओं के अधिकार और डेवलपर्स की जिम्मेदारियाँ- एक कानूनी विश्लेषण...

भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र का विस्तार केवल आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक इकाइयाँ जैसे कि दुकानें, ऑफिस स्पेस और शोरूम भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्राधिकरणों, हाउसिंग बोर्डों और निजी डेवलपर्स द्वारा दुकानों का आवंटन स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ निवेश का भी प्रमुख साधन बन चुका है। किंतु, इस प्रक्रिया में कई बार पारदर्शिता की कमी, कब्जा मिलने में देरी, अप्रत्याशित शुल्क तथा अनुबंध के उल्लंघन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। परिणामस्वरूप उपभोक्ता और डेवलपरों के बीच विवाद खड़े हो जाते हैं, जो उपभोक्ता अदालतों तक पहुँचते हैं।

इस लेख में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा, सेवा में कमी, उपायों और मध्यस्थता जैसे प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे और संबंधित न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह समझेंगे कि दुकानों के आवंटियों के क्या अधिकार हैं और डेवलपर किन उत्तरदायित्वों से बंधे हैं।

1. उपभोक्ता की परिभाषा और स्वरोजगार का महत्व

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) में उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत उपयोग अथवा स्वरोजगार के उद्देश्य से अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि, जो व्यक्ति केवल निवेश अथवा पुन: बिक्री के उद्देश्य से कोई व्यावसायिक संपत्ति खरीदता है, वह उपभोक्ता नहीं माना जाएगा।

प्रदीप सिंह पहल बनाम टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर (2016)

इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति दुकान केवल निवेश हेतु खरीदता है और यह साबित नहीं कर सकता कि वह अपनी जीविका चलाने के लिए इसका उपयोग करने वाला है, तो वह उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। इसलिए उपभोक्ता अदालत में वाद दायर करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता यह साबित करे कि उसने संपत्ति स्वरोजगार हेतु ली है।

विश्लेषण

यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि दुकानें खरीदने वाले वे व्यक्ति ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आते हैं जो स्वयं उसका उपयोग स्वरोजगार हेतु करते हैं। अत: किसी भी वाद को दायर करने से पहले, दस्तावेज़ों और तर्कों में यह बात स्पष्ट रूप से स्थापित होनी चाहिए।

2. सेवा में कमी (Deficiency in Service)

सेवा में कमी की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(11) में दी गई है, जो किसी सेवा में वादे के अनुसार गुणवत्ता, समयसीमा या निष्पादन

में कमी को दर्शाती है। दुकान आवंटन मामलों में, यह कमी सामान्यत: निम्न रूपों में देखी जाती है-

- कब्जा देने में अनावश्यक विलंब
- अधूरी निर्माण प्रक्रिया
- बिना पूर्व सूचना के शुल्क में वृद्धि
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन

कुबेर बिल्डर्स बनाम ऋषभ तिलक केमिकल्स (2021)

इस केस में शिकायतकर्ता ने लगभग छह लाख रुपये जमा किए, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी उसे कब्जा नहीं मिला। हृष्ठष्ठक्रष्ट ने इसे स्पष्ट रूप से सेवा में कमी माना और कहा कि यदि निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ, तो खरीदार को बकाया राशि का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

विश्लेषण

यह मामला उन आवंटियों के लिए उदाहरण है जिन्हें कब्जा मिलने में अनावश्यक देरी होती है। उपभोक्ता अदालत यह सुनिश्चित करती है कि यदि डेवलपर या प्राधिकरण वादा पूरा नहीं करता है, तो उसे सेवा में कमी माना जाए और खरीदार को राहत प्रदान की जाए।

3. उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध उपाय (Remedies Available)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 34 के तहत जिला उपभोक्ता आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपभोक्ताओं को निम्न राहतें प्रदान कर सके-

- वादे के अनुसार कब्जा दिलवाना
- ब्याज सहित रिफंड देना
- मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय हानि के लिए मुआवजा देना
- अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराना

कुसुम बंसल बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (2019)

इस मामले में शिकायतकर्ता को आठ वर्षों तक दुकान का कब्जा नहीं मिला। हरियाणा राज्य आयोग ने डेवलपर को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी धनराशि लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी कहा कि यदि अनुबंध की शर्तों का पूर्ण पालन नहीं हुआ है तो खरीदार से जबरन समझौता नहीं कराया जा सकता।

विश्लेषण

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और यदि पजेशन न मिले तो ब्याज सहित धनवापसी का अधिकार प्राप्त होता है।

4. अनधिकृत शुल्क वसूली का मामला

कई बार डेवलपर्स या प्राधिकरण अनुबंध के बाद ऐसे शुल्क वसूलते हैं जिनका उल्लेख मूल अनुबंध में नहीं होता। यह न केवल अनुबंध की अवहेलना है, बल्कि सेवा में कमी का एक गंभीर उदाहरण भी बन सकता है।

रामगोविंद त्रिपाठी बनाम कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण (2023)

इस प्रकरण में उपभोक्ता फोरम ने कहा कि मूल अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख न होने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क अवैध माना जाएगा। शिकायतकर्ता को ऐसे शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई और डेवलपर को अनुचित लाभ अर्जन से रोका गया।

विश्लेषण

यह फैसला उपभोक्ताओं को यह अधिकार देता है कि वे बिना आधार के लगाए गए शुल्कों को अदालत में चुनौती दे सकें और अनुचित आर्थिक बोझ से राहत पा सकें।

5. मध्यस्थता की भूमिका और अदालत के बाहर समाधान

कानूनी प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 37 के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान मध्यस्थता का है, जिसके तहत विवाद को अदालत के बाहर हल किया जा सकता है।

मध्यस्थता केंद्रों की भूमिका

राज्य और जिला स्तर पर मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं। इससे समय और खर्च की बचत होती है और अदालतों पर भार भी कम होता है।

विश्लेषण

मध्यस्थता न केवल विवाद समाधान का वैकल्पिक तरीका है, बल्कि यह न्यायपालिका पर भार को कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है। इसलिए उपभोक्ताओं को पहले मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दी जाती है।

सारांश ...

दुकानों के आवंटन में होने वाली अनियमितताएं केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि समूचे रियल एस्टेट पारिस्थितिकी तंत्र की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ताओं को ठोस कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, परंतु इस सुरक्षा का लाभ तभी मिलता है जब खरीदार स्वयं सजग हो।

- स्वरोजगार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
- कब्जा में देरी, अनुबंध उल्लंघन या अतिरिक्त शुल्क को चुनौती दी जा सकती है।
- ब्याज सहित धनवापसी या कब्जा दिलाने के लिए उपाय उपलब्ध हैं।
- मध्यस्थता का विकल्प अपनाकर समय और धन की बचत की जा सकती है।
- आज आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता कानूनी विकल्पों के प्रति सजग हों, उचित दस्तावेज रखें, और आवंटन से पूर्व सभी शर्तों को अच्छी तरह समझें। ऐसा करके ही हम एक अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी रियल एस्टेट व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

बस्तर की वीरान राहों पर लौट आई ज़िंदगी की रफ्तार

एक समय था जब छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को भारत के नक्शे पर केवल नक्सल प्रभावित इलाकों के रूप में जाना जाता था। यहाँ का नाम आते ही भय, हिंसा और अलगाव की तस्वीरें आंखों के सामने उभरती थीं। लेकिन समय बदला है, और अब बस्तर एक नई करवट ले रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने वह कर दिखाया है जो बीते 10-15 वर्षों तक केवल योजनाओं में ही सीमित था। जहाँ पहले नक्सलियों की अनुमति के बिना कोई अधिकारी या बाहरी व्यक्ति कदम भी नहीं रख सकता था, वहाँ अब बसें, जीपें और निजी वाहन धड़ल्ले से आ-जा रहे हैं।

सुरक्षा कैंपों ने बदली दिशा

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश करने का सबसे बड़ा अवरोध था सुरक्षा का अभाव। परंतु विष्णुदेव साय सरकार ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए। न केवल सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, बल्कि नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना से स्थानीय प्रशासन को पहली बार उन क्षेत्रों में पहुंचने का अवसर मिला जो अब तक नक्सलियों की मांद के रूप में जाने जाते थे। यह केवल रणनीतिक विजय नहीं, बल्कि स्थानीय जनता के विश्वास को जीतने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

इन सुरक्षा कैंपों के कारण अब प्रशासनिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से चलने लगी हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत कार्यालय फिर से खुलने लगे हैं।

सड़क निर्माण में आई अभूतपूर्व तेजी

बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण लंबे समय से ठप पड़ा था। नक्सलियों की धमकियों, हमलों और विरोध की वजह से ठेकेदार, इंजीनियर और श्रमिक काम करने से डरते थे। कई बार मशीनें जलाई गईं, सड़कों को उखाड़ दिया गया और काम रोक दिया गया। लेकिन 2023 के बाद तस्वीर तेजी से बदलने लगी।

विष्णुदेव साय सरकार ने सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सुरक्षा बलों के संरक्षण में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और वर्ष भर के भीतर सड़कों के निर्माण में दोगुनी गति आई। यह न केवल प्रशासनिक इच्छाशक्ति का परिणाम था, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का उदाहरण भी था जिसमें सुरक्षा, विकास और जनसहभागिता का अद्वितीय संतुलन रहा।

अब तक जो सड़कें केवल नक्शों पर थीं, वो अब धरातल पर दिखाई दे रही हैं। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंटा जैसे अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब डामर की सड़कों पर वाहन चलने लगे हैं।

गांवों की बदली तस्वीर

सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवनरेखा होती हैं। बस्तर के आदिवासी इलाकों में जब से सड़कें पहुंची हैं, गांवों की तस्वीर ही बदल गई है। अब ग्रामीण बाजारों तक आसानी से पहुँच पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में सहूलियत हो रही है। बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना अब पहले जैसा चुनौतीपूर्ण नहीं रहा।

जहाँ पहले गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लादकर जंगलों से बाहर लाना पड़ता था, वहाँ अब एम्बुलेंस की सुविधा है। गाँवों में सब्ज़ी, राशन और जरूरी सामान की नियमित आपूर्ति होने लगी है। यही नहीं, ग्रामीणों ने अब कृषि उपज को बाजारों में बेचना शुरू कर दिया है जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है।

आदिवासियों का प्रशासन पर बढ़ा विश्वास

विकास केवल सड़क और भवन बनाने तक सीमित नहीं होता। जब प्रशासनिक पहुँच गाँवों तक पहुँची, तो सरकार की योजनाएँ भी जमीनी स्तर पर लागू होनी शुरू हुईं। वनाधिकार पट्टों का वितरण, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ अब उन लोगों को मिल रहा है जो वर्षों से इससे वंचित थे।

आदिवासियों का प्रशासन और शासन पर विश्वास बढ़ा है। पहले जो नक्सलियों के डर से चुप रहते थे, अब वही ग्रामीण खुले मंचों पर प्रशासन से संवाद करते हैं। अब वे विकास की मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं। यह बदलाव केवल योजनाओं की वजह से नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा क्षेत्र में बनाए गए भरोसे की वजह से आया है।

नक्सल प्रभाव में आई कमी

सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती, जनता का सहयोग और लगातार हो रहे विकास कार्यों की वजह से अब नक्सली प्रभाव सीमित होता जा रहा है। कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों से भी खुफिया सूचनाएँ मिलने लगी हैं, जो पहले असंभव था।

यह बदलाव केवल बंदूक से नहीं, विकास और विश्वास के मेल से आया है। जहाँ एक ओर सुरक्षा बल मोर्चे पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और योजनाओं के क्रियान्वयन अधिकारी भी मैदान में काम कर रहे हैं।

सरकार की दूरदृष्टि और संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीति विकास ही सुरक्षा है के सिद्धांत पर आधारित है। उनका मानना है कि अगर आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और संचार के साधन मिलेंगे, तो नक्सलवाद की जमीन अपने आप खिसक जाएगी।

सरकार ने सड़क विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। नक्सल क्षेत्रों में 'कोर एरिया डेवेलपमेंट स्कीम' के अंतर्गत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल कागजी कार्रवाई न करें, बल्कि खुद गाँवों में जाएं, लोगों से बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।

अवसर और चुनौतियाँ

जहाँ एक ओर बस्तर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, वहीं कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नक्सलियों का प्रभाव बाकी है। स्थानीय स्तर पर डर और भ्रम का वातावरण खत्म करना आसान नहीं है। इसके अलावा, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। बस्तर की जैव विविधता, जंगल और संसाधनों को बचाते हुए विकास करना जरूरी है। सरकार को इस दिशा में भी सतर्क रहना होगा ताकि 'विकास' का मतलब केवल कं ीट के जंगल न बन जाएं।बस्तर का पुनर्जागरण एक प्रेरणादायक गाथा है-एक ऐसा उदाहरण जहाँ वर्षों की उपेक्षा, हिंसा और भय की भूमि को विकास, विश्वास और दृढ़ संकल्प से पुनर्जीवित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज वह सड़कों का सपना साकार हुआ है जो वर्षों से अधूरा था। जहाँ पहले नक्सलियों की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता था, वहाँ आज सरकारी अधिकारी, स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और आम नागरिक खुलकर अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। बस्तर की यह नई तस्वीर केवल सरकार की जीत नहीं, बल्कि उस आम आदिवासी की भी जीत है जो वर्षों से विकास की बाट जोह रहा था। आने वाले समय में यदि यही रफ्तार बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब बस्तर भारत के सबसे विकसित और शांतिपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाएगा।

मोदी सरकार 3.0 का एक वर्ष

परिवर्तन, प्रगति और प्रतिबद्धता का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण कर लिया है। 2014 से अब तक लगातार सत्ता में बनी रही मोदी सरकार ने अपने 11 वर्षों के शासनकाल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मोदी सरकार 3.0 के पहले वर्ष में भारत ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक मोर्चों पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो देश को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक साबित हुए हैं।

आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियाँ

1. भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। 2028 तक भारत के जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुँचने की संभावना है। यह उपलब्धि तेज़ आर्थिक विकास, सुधारात्मक नीतियों और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की रणनीतियों का परिणाम है।

2. सशक्त GDP वृद्धि

भारत की 2024-25 की चौथी तिमाही में तष्ठक्क वृद्धि दर 7.4त्न रही, जबकि वर्षभर की औसत वृद्धि दर 6.5त्न रही। यह तब हुआ जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका के टैरिफ और व्यापार अस्थिरता जैसे अनेक संकट मौजूद थे।

3. भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

6 मई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत के 99त्न निर्यात पर ब्रिटेन में शल्क नहीं लगेगा। इससे भारतीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

4. जीएसटी संग्रह का रिकॉर्ड स्तर

अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, जो जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है।

5. विदेशी मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो निवेशकों में भारत के प्रति विश्वास को दर्शाता है।

सामरिक और सुरक्षा क्षेत्र

1. ऑपरेशन सिंदूर- पाकिस्तान को करारा जवाब

22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 07 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इसमें पाकिस्तान और पीओजेके के भीतर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।

2. हवाई ठिकानों पर जवाबी हमला

09 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें उसकी वायुसेना की 20त्न संपत्ति नष्ट हो गई। यह पहली बार था जब भारत ने परमाणु संपन्न देश के भीतर इतने व्यापक पैमाने पर हमला किया।

3. भारत-चीन सैन्य गतिरोध का समाधान

जुलाई 2024 से चली बातचीत के बाद अक्टूबर में भारत और चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर समझौता हुआ और दिसंबर में विदेश मंत्री जयशंकर ने औपचारिक रूप से सैन्य वापसी की घोषणा की।

राजनीतिक परिदृश्य

1. दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी जीत

- दिल्ली-27 वर्षों के बाद भाजपा ने राजधानी में 70 में से 48 सीटें

जीतकर सत्ता में वापसी की।

- महाराष्ट्र- महायुति गठबंधन ने 132 सीटों पर विजय हासिल की।
- हरियाणा- भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई।

2. जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी

10 वर्षों बाद हुए विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए, जिसमें INDIA गठबंधन को बहुमत मिला। इससे क्षेत्र में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं।

3. एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक

दिसंबर 2024 में सरकार ने यह ऐतिहासिक विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिससे चुनावी प्रक्रिया को समग्र और लागत प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा।

प्रमुख नीतिगत निर्णय और योजनाएं

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार

10 जून 2024 को सरकार ने 3 करोड़ नए ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण में सहायता देने का फैसला किया, जिससे गरीबों को अपना पक्का घर मिल सकेगा।

2. सार्वजनिक परीक्षा सुरक्षा कानून

21 जून 2024 से लागू हुआ यह कानून परीक्षा में पेपर लीक या धोखाधड़ी जैसे मामलों में 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

3. नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन

01 जुलाई 2024 से 'भारतीय न्याय संहिता', 'नागरिक सुरक्षा संहिता' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' लागू किए गए, जो पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह लेंगे।

4. इंटर्नशिप योजना

23 जुलाई को नई योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल प्रदान किया जाएगा।

5. एकीकृत पेंशन योजना

24 अगस्त 2024 को पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू की गई, जो उन्हें अंतिम वेतन का 50ब मासिक पेंशन के रूप में देगी।

विज्ञान, तकनीक और कृषि क्षेत्र

1. बायोई3 नीति और विज्ञान धारा योजना

24 अगस्त को बायोटेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी योजनाएं लागू की गईं, जिनमें बायोमैन्युफैक्चरिंग, बायो-एआई हब और आरएंडडी को नवाचार के साथ जोड़ने पर बल दिया गया।

2. कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार

28 अगस्त को पीएम-कुसुम और एफपीओ ऋण गारंटी के साथ एआईएफ को जोड़ा गया। इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा।

3. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 100 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता और ऋण पहुंच को सुधारने की घोषणा की गई।

रक्षा और बुनियादी ढांचा

1. INS अरिघात की तैनाती

29 अगस्त को भारत की दूसरी न्यूक्लियर-सबमरीन आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल किया गया, जिससे समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली।

2. वधावन पोर्ट परियोजना

30 अगस्त को 76220 करोड़ की लागत से वधावन मेगा पोर्ट की आधारशिला रखी गई, जिससे भारत के समुद्री व्यापार को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा मिल सकेगी।

3. चिनाब ब्रिज का उद्घाटन

6 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन किया, जो इंजीनियरिंग का अद्वितीय नमूना है।

सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य

1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत का विस्तार

11 सितंबर को 70 वर्ष और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया।

2. ई-ड्राइव योजना

11 सितंबर को पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, ई-ट्रक और स्क्रैप नीति शामिल है। यह हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण पहल है।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ

- तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण- 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका से भारत लाया गया।
- लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन- प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने हेतु जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग को नए जिले घोषित किया गया।

मोदी सरकार 3.0 का पहला वर्ष जनकल्याण, राष्ट्रहित और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेज़ी से बढ़ता हुआ काल रहा। चाहे वह आर्थिक मोर्चे पर हो, सामाजिक सुधारों में, विज्ञान एवं रक्षा क्षेत्र में, या अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि सुदृढ़ करने में — सरकार ने निर्णायक नेतृत्व और दूरदर्शिता का परिचय दिया। यह वर्ष यह भी दर्शाता है कि आने वाला समय भारत के लिए संभावनाओं और अवसरों से भरपूर होगा।

स्कूलों का युक्तियुक्तकरण छत्तीसगढ़ में शैक्षिक क्रांति की ओर एक निर्णायक कदम

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शैक्षणिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भावना के अनुरूप है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार होगा।

युक्तियुक्तकरण का तात्पर्य है- संसाधनों का न्यायसंगत, समन्वित और कुशल तरीके से उपयोग। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत राज्य की 5849 ई-संवर्ग और 4614 टी-संवर्ग की शालाओं को मिलाकर कुल 10,463 विद्यालयों का पुनर्गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य ऐसे विद्यालयों को एकीकृत करना है जो एक ही परिसर में संचालित होते हैं या भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत निकट हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और सराहना- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग के इस फैसले को एक दूरदर्शी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि एक ही परिसर में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों का समायोजन न केवल प्रशासनिक रूप से उपयोगी है, बल्कि इससे छात्रों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी और ड्रॉपआउट की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा।

स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत एक ही परिसर में संचालित 10,297 शालाओं का समायोजन किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर और शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में स्थित क्रमशः 133 और 33 विद्यालयों को भी युक्तियुक्त किया गया है। इस निर्णय से अब उन विद्यालयों में भी शिक्षक उपलब्ध होंगे जो अब तक शिक्षकविहीन या एकल शिक्षक आधारित थे। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता से अन्य जरूरतमंद विद्यालयों में भी संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।

शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार- इस कदम से शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को संतुलित किया जा सकेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार होगा। शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षण सामग्री का उचित वितरण, और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने जैसे कई आयाम इस योजना से जुड़ते हैं। इससे छात्रों को बार-बार विद्यालय बदलने या प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी।

युक्तियुक्त विद्यालय परिसरों में साझा अधोसंरचना विकसित की जाएगी, जिसमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल परिसर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा के संसाधनों तक सहज पहुंच मिलेगी और शिक्षकों के लिए भी शिक्षण अधिक प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त स्थापना व्यय में कमी आने से सरकार अधिक धनराशि शैक्षणिक ढांचे के विकास में निवेश कर सकेगी।

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 'क्लस्टर विद्यालय' मॉडल के अनुरूप है। इस मॉडल के अंतर्गत एकीकृत परिसर में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। इससे छात्रों को एक स्थिर और निरंतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होता है, जिससे वे बिना किसी व्यवधान के अपने शैक्षणिक सफर को तय कर सकते हैं।

शिक्षा सचिव के अनुसार, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय किया गया है, न कि किसी पद को समाप्त किया गया है। इससे शिक्षकों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में आसानी होगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार छात्रों और शिक्षकों के अनुपात का पालन किया गया है, जो कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बच्चों के लिए एक सहज और निरंतर शिक्षा यात्रा- इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। एक ही परिसर में अध्ययन करने से उन्हें हर स्तर पर शिक्षा के लिए नए विद्यालय में प्रवेश नहीं लेना पड़ेगा। इससे छात्रों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा वे अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर सकेंगे। यह कदम ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को और सुलभ बनाएगा, जिससे सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा में समावेशी विकास की नई इबारत- छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इससे न केवल वर्तमान शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समावेशी, स्थायी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी जाएगी। यह प्रयास न केवल शैक्षणिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मद्दी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मद्दी सामाजिक रूप से लंबे समय से सक्रिय हैं और उनके पास विभिन्न पदों पर कार्य करने का गहरा अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनका यह अनुभव स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के कार्यों को सुदृढ़ करने में उपयोगी सिद्ध होगा। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अनेक नवाचारों के माध्यम से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता ला रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापना और विकास के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नक्सल उन्मूलन के साथ-साथ हम बस्तर में अधोसंरचना और पर्यटन विकास के कार्यों को गति दे रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें। हमने हाल ही में दुधारू पशु योजना के माध्यम से आदिवासी परिवार को दो अच्छी नस्ल की गाय प्रदान करने की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से हुई मुलाकात में प्रदेश के विकास को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से बस्तर में सिंचाई परियोजनाओं और इंद्रावती एवं महानदी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी पहल के बारे में सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के साथ-साथ यह विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि श्री श्रीनिवास के सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव का लाभ निश्चित ही बेवरेजेस कॉर्पोरेशन को मिलेगा। उन्हें पहले भी वन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला था और उन्होंने बेहतर ढंग से दायित्व का निर्वहन किया। इस अवसर पर नई जिम्मेदारियों के लिए उन्होंने श्री मद्दी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक श्री किरण देव ने भी संबोधित किया एवं शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सांसद श्री महेश कश्यप, सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री आशाराम नेताम, विधायक श्री चैतराम अटामी, विधायक श्री विनायक गोयल, विधायक श्री धरमलाल कौशिक एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

विष्णु देव साय के सुशासन में लोगों को समस्याओं के समाधान का भरोसा- उप मुख्यमंत्री अरुण साव

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की एक नई मिसाल स्थापित हो रही है। इसका प्रमाण हाल ही में बेमेतरा जिले के ग्राम जेवरी में आयोजित समाधान शिविर में देखने को मिला, जहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके समाधान की दिशा में त्वरित निर्णय भी लिए। यह शिविर 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत आयोजित किया गया था।

इस शिविर में उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह है। उन्होंने कहा, अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सरकार खुद उनके गांवों तक पहुंच रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि लोगों को सरकार पर विश्वास है और वे अपनी समस्याएं खुलकर सामने रख रहे हैं।

शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्राम जेवरी और आसपास के गांवों के लिए 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें शामिल हैं-

- जेवरी और बैजलपुर ग्राम पंचायतों में गौरव पथ निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए
- जेवरी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख रुपए
- फरी, खिलोरा और अमोरा ग्राम पंचायतों में सीसी सड़क निर्माण के लिए 8 लाख रुपए
- फरी (तेलाईकुड़ा), डुंडा, निनवा, रजकुड़ी (भीमपुरी), कंतेली और फरी में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की घोषणा

इस तरह की घोषणाएं यह दिखाती हैं कि राज्य सरकार केवल वादे नहीं कर रही, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस काम कर रही है।

शिविर में उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति तथा लाभार्थियों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचे।

उदाहरणस्वरूप, दिव्यांगजन श्री रामकृष्ण मार्कण्डेय को ट्राइसिकल प्रदान की गई। इसके अलावा-

- पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड
- महिलाओं को नोनी सुरक्षा पासबुक
- वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड
- किसानों को स्प्रेयर मशीन
- बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार
- गर्भवती महिलाओं को पोषण किट भी वितरित की गई।

ये सभी क्रियाएं एक ही स्थान पर सम्पन्न हुईं, जिससे ग्रामीणों को एक दिन में कई समस्याओं का समाधान मिला।

प्रधानमंत्री की गारंटियों को निभा रही सरकार

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को बताया

कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभी गारंटियों को राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा-

- धान खरीदी 3100 प्रति क्विंटल की दर पर
- किसानों को बोनस वितरण
- महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता
- इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है- ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करना।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित यह समाधान शिविर राज्य में सुशासन का नया मॉडल बनकर उभरा है। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, बल्कि अधिकारी स्वयं गांवों में जाकर उनकी समस्याएं सुन और सुलझा रहे हैं।

इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सरकार और जनता के बीच

विश्वास की डोर मजबूत हुई है। गांव के साधारण नागरिक को अब यह भरोसा है कि सरकार उनकी समस्याएं सुनेगी और समाधान देगी। इस समाधान शिविर की खास बात यह रही कि इसमें क्लस्टर के 12 ग्राम पंचायतों के निवासियों की समस्याएं सुनी गईं और उनका समाधान भी किया गया। यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि जनभागीदारी और जनसरोकार का वास्तविक मंच था। समाधान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। बेमेतरा के कलेक्टर श्री रणवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने शिविर में सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके साथ ही पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इन सभी की भागीदारी ने कार्यक्रम को प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाया।

समाधान शिविर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव का वक्तव्य बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने कहा, हमारी सरकार गरीब, किसान और गांव के विकास के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लोगों को यह भरोसा है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा — क्योंकि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है।

इस प्रकार यह समाधान शिविर न केवल प्रशासनिक दक्षता का परिचायक बना, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जब सरकार संवेदनशील और सक्रिय होती है, तो उसका असर सीधे जनता के जीवन पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में चल रहा 'सुशासन तिहार' एक राजनीतिक या प्रतीकात्मक आयोजन नहीं, बल्कि जनसेवा का जीवंत उदाहरण बनता जा रहा है।

सरकार की यही प्रतिबद्धता अगर इसी तरह बनी रही, तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के सबसे सुशासित राज्यों में शुमार होगा।

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी

- खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा-हमारे युवाओं के पास अब विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे। इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

रजिस्ट्री प्रक्रिया में 10 क्रांतिकारी बदलाव- छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल...

छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए संपत्ति से जुड़े रजिस्ट्री कार्य को अधिक सरल, सुविधाजनक, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और पंजीयन विभाग के मंत्री श्री ओ पी चौधरी के मार्गदर्शन में राज्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया में 10 क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। इस नई व्यवस्था की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की विशेष उपस्थिति रही।

यह कार्यशाला कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची, कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, अधिवक्तागण, व्यापारी, पत्रकार, अधिकारी एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन में मास्टर ट्रेनर उप-पंजीयक श्री योगेन्द्र पटेल ने प्रस्तुति के माध्यम से रजिस्ट्री प्रणाली में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी दी।

पृष्ठभूमि- क्यों आवश्यक थे ये बदलाव?

पहले की रजिस्ट्री प्रक्रिया जटिल, समय-लेवा और भ्रष्टाचार से ग्रस्त मानी जाती थी। फर्जीवाड़े, नकली दस्तावेज, बार-बार दफ्तरों के चक्कर, पटवारियों पर निर्भरता, बटवारे में अनावश्यक अड़चनें और तकनीकी जटिलताएँ आम लोगों को भारी परेशानियों में डालती थीं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को केंद्र में रखकर इस प्रक्रिया में बदलाव किए हैं।

10 क्रांतिकारी बदलाव

1. आधार सत्यापन से फर्जी रजिस्ट्री पर रोक

अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों का आधार से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फर्जी व्यक्ति या अवैध दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री करना असंभव हो गया है। इससे कानूनी विवादों में भारी कमी आने की संभावना है।

2. रजिस्ट्री खोज और डाउनलोड सुविधा

कोई भी नागरिक अब अपनी या किसी भी सार्वजनिक रजिस्ट्री को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खोज और डाउनलोड कर सकता है। इससे पुराने रिकार्ड खोजना, प्रमाण देना और दस्तावेज दिखाना बेहद आसान

हो गया है।

3. ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र (Loan Clearance Certificate)

अगर संपत्ति पर कोई ऋण नहीं है, तो उसका प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन ही जारी हो जाता है। पहले इसके लिए बैंकों और विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब यह काम चंद क्लिक में हो जाता है।

4. स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान

अब स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम (PI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि) से किया जा सकता है। नकद लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियों पर इससे रोक लगेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है।

5. व्हॉट्सएप सेवाएं

अब पंजीयन विभाग की कई सेवाएं व्हॉट्सएप पर उपलब्ध हैं। पंजीकृत नंबर पर संदेश भेजकर लोग जरूरी जानकारी, स्टेटस अपडेट, दस्तावेज की स्थिति आदि जान सकते हैं। यह सेवा लोगों की सुविधा के लिहाज से बड़ी क्रांति मानी जा रही है।

6. डिजी लॉकर सेवाएं

रजिस्ट्री दस्तावेज अब सीधे डिजी लॉकर में अपलोड किए जा रहे हैं। इससे किसी भी समय, किसी भी स्थान से दस्तावेज को डाउनलोड किया जा सकता है और उसकी वैधता भी सुनिश्चित होती है। इससे सरकारी सेवाओं में उपयोग भी आसान हो गया है।

7. रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण

रजिस्ट्री के दस्तावेज अब स्वचालित सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं। इससे मानवीय त्रुटियाँ, टाइपिंग की गलतियाँ और कागजों की गड़बड़ी लगभग समाप्त हो गई है।

8. घर बैठे स्टांप सहित दस्तावेज निर्माण

अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन स्टांप खरीद सकते हैं और दस्तावेज भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसी बिचौलिए या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि प्रक्रिया अधिक आत्मनिर्भर भी बनती है।

9. घर बैठे रजिस्ट्री सेवा

राज्य सरकार ने तकनीक के माध्यम से अब नागरिकों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है।

10. रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण

यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाती है। पहले इसके लिए अलग से आवेदन, पटवारी की रिपोर्ट, तहसील कार्यालय के चक्कर और महीनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब यह प्रक्रिया एकीकृत कर दी गई है।

पारिवारिक बटवारे में सुधार

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यशाला में बताया कि पैतृक संपत्ति के पारिवारिक बटवारे की रजिस्ट्री अब केवल 500 रूपए में संभव हो गई है। यह पहले एक जटिल और महंगा कार्य माना जाता था। साथ ही, जिओ टेगिंग के माध्यम से पेड़ों की संख्या और स्थिति स्पष्ट हो जाने पर उनकी कीमत को शून्य मानकर बोझ को कम कर दिया गया है।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि इस बदलाव से लोगों का समय, श्रम और धन बचेगा और सरकारी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने मीडिया से इस क्रांतिकारी सुधार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की अपील की।

विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची ने कहा कि वीडियो के माध्यम से जो प्रक्रिया दिखाई गई, वह वास्तव में प्रभावशाली और सरल है। जनता इसका भरपूर लाभ उठाएगी।

कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि यह पहल जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है। डिजिटलीकरण से प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी और विभागीय भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया में किया गया यह क्रांतिकारी सुधार राज्य को डिजिटल इंडिया के सपनों के करीब ले जाता है। यह न केवल नागरिकों को सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि प्रशासन की दक्षता और जवाबदेही को भी बढ़ाता है।

यह बदलाव आने वाले समय में ई-गवर्नेंस की नई मिसाल बनेगा और अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। आम जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक, अब बिना डर और झंझट के संपत्ति से जुड़े कार्य कर सकेंगे।

सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया अगर मिलकर इस व्यवस्था को जन-जन तक पहुँचाएं, तो यह बदलाव वास्तव में संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन साबित होगा।

हरित ऊर्जा की ओर छत्तीसगढ़ का सशक्त कदम

कचरे से कमाई की राह- रायपुर में बनेगा आधुनिक बायोगैस संयंत्र

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। रायपुर नगर निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके तहत रायपुर के रांवाभाटा ग्राम में एक अत्याधुनिक कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

यह समझौता भारत सरकार की SATAT योजना (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य है नगरीय ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करना और परिवहन के लिए वैकल्पिक, सस्ती और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना।

हरित भविष्य की आधारशिला

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हरित ऊर्जा और स्वच्छ पर्यावरण को अपनी नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह बायोगैस संयंत्र केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आत्मनिर्भर और पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त भविष्य की आधारशिला है।

रांवाभाटा में प्रस्तावित संयंत्र में प्रतिदिन 100 से 150 टन मिश्रित ठोस अपशिष्ट (MSW) का प्रसंस्करण होगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला बायोगैस तैयार किया जाएगा। इस परियोजना में पूंजी निवेश करीब 100 करोड़ रुपए का होगा, जो पूर्णतः BPCL द्वारा किया जाएगा।

संयंत्र की विशेषताएं और संभावनाएं

- **रोजगार सृजन**

संयंत्र के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30,000 मानव दिवस प्रतिवर्ष का रोजगार सृजित होगा। इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे।

- **पर्यावरणीय लाभ**

संयंत्र ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ को हृद्गह ´द्गह्श्च श्चद्वद्धह्यद्धह्यद्बश्ठ लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम और आगे ले जाएगी।

- **राजस्व सृजन**

संयंत्र जब अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा, तब इससे राज्य को वार्षिक लगभग 1 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। यह राजस्व राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता को और मजबूती देगा।

- **जैविक कृषि को बढ़ावा**

संयंत्र से सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी, जिससे जैविक खेती को नया प्रोत्साहन मिलेगा और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी।

राज्यव्यापी बायोगैस क्रांति

रायपुर से पहले वर्ष 2024 में भिलाई नगर पालिक निगम के साथ भी एक त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है। इसके बाद 2025 में अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी और बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी CBG संयंत्रों की स्थापना हेतु समझौते किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के विभिन्न भागों में अपशिष्ट प्रबंधन को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ठोस कदम उठा रही है।

रायपुर की नई पहचान

राजधानी रायपुर अब सिर्फ प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा और स्मार्ट कचरा प्रबंधन की मिसाल बनकर उभरने को तैयार है। इस संयंत्र से न केवल शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह परियोजना कचरे से कमाई की व्यवहारिक अवधारणा को साकार रूप देगी।

छत्तीसगढ़ का यह कदम न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक प्रेरणास्पद मॉडल बन सकता है। जहां एक ओर नगरीय कचरे की समस्या विकराल रूप ले रही है, वहीं इस प्रकार की परियोजनाएं यह दिखाती हैं कि सही नीति, तकनीक और निवेश से कचरे को संपदा में बदला जा सकता है। रायपुर का यह बायोगैस संयंत्र एक ऐसा ही हरित परिवर्तन है, जो छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के क्षेत्र में जिम्मेदार राज्य बनने की ओर अग्रसर करेगा।

हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार- मुख्यमंत्री साय

बस्तर के नारायणपाल में लगाई चौपाल, जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हर जरूरतमंद के साथ राज्य सरकार खड़ी है, जनकल्याण ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन मतलब है अच्छा शासन। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बस्तर जिले के ग्राम नारायणपाल पहुंचे। उन्होंने नारायणपाल के देवगुड़ी परिसर में आम के पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई और ग्रामीणों से जीवंत संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बिजली व्यवस्था, राशन वितरण, पीएम आवास योजना और महतारी वंदन योजना के साथ ही गांव में राशन कार्ड की स्थिति, राशन की उपलब्धता, शिक्षकों और पटवारियों की उपस्थिति जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी जानकारी ली। 'महतारी वंदन योजना' की लाभार्थी श्रीमती सरिता कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, महतारी वंदन से मिलने वाली राशि का उपयोग घरेलू खर्चों और बच्चों के इलाज में करती हैं। श्री जगमोहन कश्यप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण पूरा होने की जानकारी दी। श्रीमती ललिता बघेल ने बताया कि पहले उन्हें बेल मेटल का काम करने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे। अब बिहान योजना के तहत उन्हें 15,000 रूपए की सहायता और बैंक से 1.5 लाख रूपए तक का ऋण मिल रहा है, जिससे उनका काम बेहतर तरीके से चल रहा है। श्रीमती पदमिनी ठाकुर ने बताया कि वे ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के निर्माण से जुड़ी हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को फूड बास्केट भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जरूरतमंदों को आवास मिलेगा, 'आवास प्लस' में जिनका नाम है, उन्हें भी आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'महतारी वंदन योजना' में जिन महिलाओं का नाम नहीं जुड़ा है, उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर रही है। पंजीयन की नई प्रक्रिया से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। जल्द ही इसका विस्तार सभी ग्राम पंचायतों में होगा।

अनेक विकास कार्यों की घोषणा

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर अनेक घोषणाएं की, जिनमें नारायणपाल माध्यमिक शाला भवन के लिए 20 लाख रूपए, प्राथमिक शाला मंदिरपारा के लिए 20 लाख रूपए, स्ट्रीट लाईट, हाई मास लाईट के लिए 15 लाख रूपए, व्यावसायिक परिसर हेतु 20 लाख रूपए, सी.सी. रोड 600 मी. (गोवर्धन भाटा से बोधघरा घर तक) 15 लाख रूपए, पुलिया 2 मी. स्पान 2 नग के लिए 12 लाख रुपए, सी.सी सड़क धरमु घर से नाव घाट तक 9 लाख रूपए, इस प्रकार कुल 1 करोड़ 11 लाख रूपए की लागत के कार्यों की घोषणा की। नारायणपाल में मुख्यमंत्री ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की वन समिति के 11 हितग्राहियों को वाहन का वितरण किया। इसमें कोटमसर, तीरथगढ़ और कामानार के वन समिति के हितग्राही शामिल थे। उन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और किताबें देकर सम्मानित किया।

DIGIPIN: डिजिटल भारत की एड्रेसिंग क्रांति...

भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है- DIGIPIN (Digital Postal Inde& Number) का शुभारंभ। भारतीय डाक विभाग द्वारा 27 मई 2025 को लॉन्च किया गया यह नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम न केवल पारंपरिक पते की सीमाओं को पार करता है, बल्कि भारत के हर कोने तक डिजिटल सेवाओं की सटीक पहुंच सुनिश्चित करता है।

क्या है DIGIPIN?- DIGIPIN एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है जो भारत के प्रत्येक स्थान को केवल 4×4 मीटर के क्षेत्र मंस सटीक रूप से परिभाषित करता है। यह पिनकोड प्रणाली का तकनीकी उन्नयन है जो अब तक संपूर्ण क्षेत्रों या कस्बों के स्तर पर काम करता था। DIGIPIN सिस्टम ओपन-सोर्स और भू-स्थानिक (Geo-coded) तकनीक पर आधारित है, जिसे भारतीय डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और ISRO के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के सहयोग से विकसित किया है।

कैसे काम करता है DIGIPIN?- DIGIPIN अक्षांश (Latitude) और देशांतर (Longitude) के डेटा का उपयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक स्थान को, चाहे वह किसी घने शहरी क्षेत्र में हो या किसी दूरदराज़ ग्रामीण क्षेत्र में, एक निश्चित डिजिटल कोड से जोड़ा जा सकता है।

उपयोगकर्ता https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home पोर्टल पर जाकर अपना स्थान डालकर DIGIPIN प्राप्त कर सकते हैं। GPS सक्षम डिवाइस की सहायता से या मैन्युअल रूप से लोकेशन का विवरण डालकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यह प्रणाली ऑफलाइन भी काम कर सकती है, क्योंकि इसका कोड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

मुख्य लाभ

1. सटीक डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स- DIGIPIN की सहायता से ई-कॉमर्स, कूरियर और पार्सल सेवाएं अब अधिक सटीकता और तेज़ी से डिलीवरी कर सकेंगी। अस्पष्ट पते या असंगठित बस्तियों में भी यह सुविधा काम करेगी।

DIGIPIN बनाम पारंपरिक पिनकोड

विशेषता	पारंपरिक पिनकोड	DIGIPIN
दायरा	बड़े क्षेत्र (शहर, मोहल्ला)	4×4 मीटर का सटीक स्थान
प्रकार	संख्यात्मक (Numeric)	अल्फान्यूमेरिक (10-अंकीय)
तकनीक	क्षेत्र आधारित	जियोस्पेशियल, ओपन-सोर्स
उपयोगिता	सामान्य डाक सेवाएं	सटीक डिलीवरी, नेविगेशन, आपात सेवाएं

2. आपातकालीन सेवाओं में क्रांति- पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसी सेवाएं अब कॉलर द्वारा बताई गई DIGIPIN के आधार पर सटीक स्थान पर बिना किसी देरी के पहुंच सकेंगी। यह विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं या ग्रामीण इलाकों में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. डिजिटल गवर्नेंस- DIGIPIN, (Address-as-a-Service) (AaaS) का हिस्सा बनकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आम नागरिक तक सही ढंग से पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

4. समावेशिता और ग्रामीण सशक्तिकरण- भारत के लाखों ग्रामीण या झुग्गी क्षेत्रों में जहां स्थायी पता नहीं होता, वहां DIGIPIN डिजिटल पहचान और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा।

Know Your DIGIPIN और Know Your PIN Code प्लेटफॉर्म

लॉन्च के साथ ही दो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स — Know Your DIGIPIN ¥õÚU Know Your PIN Code — भी शुरू किए गए हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को उनके डिजिटल और पारंपरिक पिन कोड के बारे में जानकारी देना है।

तकनीकी पृष्ठभूमि और नीतिगत आधार- DIGIPIN का विकास भारत सरकार की नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत किया गया है। यह नीति भारत में भू-स्थानिक डेटा के बेहतर प्रबंधन और उपयोग को बढ़ावा देती है, जो स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और जन सेवा जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएं

- **निजी क्षेत्र में उपयोग-** डिलीवरी सेवाएं, ride-sharing ऐप्स, फूड डिलीवरी और यहां तक कि स्वास्थ्य सेवाएं भी DIGIPIN को अपनाकर संचालन की सटीकता बढ़ा सकती हैं।
- **शहरी नियोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर-** नगर निकाय अपने क्षेत्रों की बेहतर मैपिंग और संसाधन वितरण में DIGIPIN का उपयोग कर सकते हैं।
- **पते का डिजिटल रूपांतरण-** भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हमें अपने पते की जगह केवल DIGIPIN बताना पड़े।

DIGIPIN केवल एक डिजिटल कोड नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक दूरगामी कदम है। यह पारंपरिक पते की सीमाओं को पार करते हुए एक ऐसे युग की शुरुआत करता है जहां सटीकता, पहुंच और पारदर्शिता केंद्र में होंगी।

डिजिटल इंडिया अब केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी या ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित नहीं है — यह अब देश के हर कोने को डिजिटल पहचान देने की दिशा में बढ़ चुका है।

अपमान को गर्व में कैसे बदल सकते हैं...?

जाकर पूछो, मैं दावा करता हूं अगर वो 'मम्माज़ बॉय' बाहर जाने के लिए हां कह दे' कॉलेज कैंपस के पास सड़क किनारे चलते हुए मैंने दो लोगों की ये बातचीत सुनी, जहां वे एक युवा की ओर इशारा करते हुए उसके नाम से उसका विवरण समझा रहे थे।

वे लोग उसे ताना मार रहे थे (कह सकते हैं कि उसका अपमान कर रहे थे) कि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी वो अपनी मां की मर्जी के बिना एक इंच भी नहीं हिलेगा। वो भी ज्यादा दूर नहीं था कि कमेंट सुनाई न दे। पर वो वहां से हिला नहीं। उसने ऑटोरिक्शा रुकवाया और चला गया। और फिर खिल्ली उड़ा रहे युवकों में से एक ने कहा, 'देखा?'

इससे मुझे एक अमेरिकी शो ÷जियोपार्डी' के हालिया एपिसोड की याद आ गई। यह क्विज प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर खेला जाता है, जहां इसके होस्ट केन जेनिंग्स प्रतिभागियों का परिचय कुछ इसी तरह इंसल्ट करते हुए देते हैं। असल में एपिसोड शुरू होने से पहले प्रतिभागी खुद होस्ट से ऐसा करने का आग्रह करते हैं।

केन ने 27 वर्षीय ब्रेंडन लिया का परिचय 'रीसेंट ग्रेजुएट एंड स्टे-एट-होम सन' के तौर पर दिया। 'स्टे-एट-होम सन', साल 2007 में डिक्शनरी में अपमानस्वरूप शब्द के रूप में जुड़ा, जिसका मतलब होता है, बिना मोटिवेशन के घर पर रहने वाला बच्चा। ब्रेंडन ने शुरुआत से जियोपार्डी शो को उसी तरह देखा, जैसे बाकी कॉलेज जाने वाले बच्चे देखते थे।

चूंकि ब्रेंडन को सभी सवालों के जवाब पता होते थे, इसलिए उसने लक्ष्य बनाया कि वह शो पर जाएगा और रकम जीत लेगा। इसमें शामिल होने के इच्छुक प्रतिभागियों को 50 प्रश्नों के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। पास होने पर 50 प्रश्नों का एक और ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर ऑडिशन होता है।

इसके बाद दूसरे संभावित प्रतिभागियों के साथ मॉक गेम होते हैं और इसके बाद प्रोड्यूसर्स के पास उन प्रतिभागियों को फोन करने और शो पर बुलाने के लिए 18 महीने का समय होता है। ब्रेंडन ने 2018 में पहली बार ऑडिशन दिया था। इसके बाद 2021 और फिर 2023 के अंत में। उन्हें चार हफ्ते पहले कॉल आया और उन्होंने इस दौरान बजर के साथ जितना हो सकती थी, उतनी जमकर तैयारी की।

पिछले हफ्ते उनका एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें वह जियोपार्डी के विजेता घोषित किए गए। ब्रेंडन ने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और पिछले हफ्ते प्रसारित तीन कॉन्टेस्ट में 59,398 डॉलर (51 लाख रु.) जीते, जहां उसने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए मध्य काल के इतिहास से लेकर पॉप म्यूजिक तक के सवालों के सही जवाब दिए।

खुद का उपहास करने वाले उसके हास्य ने उसे सोशल मीडिया पर रातों-रात प्रसिद्ध बना दिया और लोग कह रहे हैं कि वह बहुत हद तक उनके सपने को जी रहा है, भले ही वह बेरोजगार है और अपने माता-पिता के साथ रहता है। अमेरिकी संस्कृति में 18 साल की उम्र के बाद माता-पिता के साथ रहना अप्रत्यक्ष रूप से अपमान माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता।

ब्रेंडन की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी उसे प्रभावित नहीं करती। उसका मानना है कि उसे जीवन भर पढ़ी गई किताबों, देखे गए टीवी, फिल्मों, समाचारों पर ध्यान देकर अर्जित ज्ञान को भुनाना चाहिए। इससे मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की भी याद आ गई। कॉलेज में लोग मुझे अन्ना कहकर बुलाते थे। कई दिनों तक मैं गुस्से में रहता था। जो लड़के मुझे चिढ़ाते थे, वे दक्षिण के नहीं थे और उस समय यह शब्द 'मद्रासी' का पर्याय था।

मेरी मां ने एक बार कहा, जब भी तुम 'अन्ना' सुनो, गर्व महसूस करो और उस व्यक्ति से कहो हां बोलो थंबी (अन्ना का मतलब बड़ा भाई और थंबी का मतलब छोटा भाई होता है)। जब मुझे मेरी पहली नौकरी मिली और मैंने मुंबई में तत्कालीन प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया, तो उसी 'अन्ना' शब्द की टोन सम्मानजनक हो गई और मेरे नाम में गर्व जोड़ दिया। फंडा यह है कि कॉलेज जाने वाले अधिकांश युवाओं को उनके दोस्त या दुश्मन, कोई न कोई नाम जरूर देते हैं। अगर यह आपको अपमान जैसा लगता है, तो धैर्य रखें, सफलता की ओर बढ़ें और वे उपलब्धियां उन्हीं तथाकथित अपमानजनक शब्दों को गर्व में बदल देंगी।

छत्तीसगढ़ में झरने Waterfalls in Chhattisgarh in Hindi: नाम, स्थान, ऊँचाई और महत्व के बारे में सब कुछ जानें!

छत्तीसगढ़ की हरी-भरी हरियाली और प्राचीन परिदृश्यों के बीच स्थित, लुभावने झरनों का खजाना उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो प्रकृति की भव्यता से रूबरू होना चाहते हैं। छत्तीसगढ़, जिसे अक्सर भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए बल्कि अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मनाया जाता है। इसके कई प्राकृतिक आश्चर्यों के बीच,छत्तीसगढ़ में झरनें (Waterfalls in Chhattisgarh in Hindi) केंद्र स्तर पर हैं, जो यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांत मुक्ति और एक दृश्य आनंद प्रदान करते हैं। इस लेख में, हम छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध और मनोरम झरनों की खोज करने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं, और उनकी राजसी सुंदरता को देखने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की खोज करते हैं। चाहे आप उत्साही साहसी हों या अवकाश यात्री, ये व्यापक चमत्कार आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ बेहतरीन झरनों में चित्रकोट झरने, तीरथगढ़ झरने, चित्रधारा झरने, चर्रे मर्रे झरने, घटारानी झरने और कई अन्य झरने शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध झरने

छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़, मेंदरी घूमर, अमृतधारा और राजपुरी झरने सहित लुभावने झरनों का खजाना है, प्रत्येक अपने आप में एक प्राकृतिक आश्चर्य है। सूची यहीं ख़त्म नहीं होती; छत्तीसगढ़ में रानी दह, टाइगर पॉइंट, रकसगंडा, केंदई, देवधारा और कैलाश गुफा झरने भी हैं, जो खोजकर्ताओं को इस सुरम्य राज्य की शोभा बढ़ाने वाले झरने के विविध सौंदर्य को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ में झरनें (Waterfalls in Chhattisgarh in Hindi) की सूची नीचे दी गई है।

चित्रकोट झरना | Chitrakoot Waterfalls

छत्तीसगढ़, भारत का एक प्रमुख पारिस्थितिक पर्यटन स्थल, विविध प्राकृतिक परिदृश्यों को समेटे हुए है, जिसमें चित्रकोट झरना भी शामिल है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे झरनों में से एक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक प्राकृतिक झरना, चित्रकोट, जगदलपुर के पश्चिमी भाग में स्थित है और एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है। चित्रकूट अपने आश्चर्यजनक सूर्यास्त और झरने के विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों को उस क्षण मंत्रमुग्ध कर देता है, जब वे उस पर नज़र डालते हैं। यह जगदलपुर क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपनी लुभावनी सुंदरता और प्राकृतिक आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करता है।

तीरथगढ़ झरने | Tirathgarh Waterfalls

तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में एक अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जो मनोरंजन, मौज-मस्ती, पिकनिक और रोमांच का मिश्रण पेश करता है। ये झरने जगदलपुर के शीर्ष पिकनिक स्थलों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं और आगंतुकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात की एक विशिष्ट विशेषता इसकी झरना संरचना है, जहां पानी नीचे उतरते ही कई धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिससे एक मनमोहक दृश्य बनता है। यह ब्लॉक-प्रकार का झरना एक ही बूंद में प्रभावशाली ढंग से 300 फीट नीचे गिरता है, जो इस स्थल के प्राकृतिक आश्चर्य को बढ़ाता है।

चित्रधारा झरना | Chitradhara Falls

चित्रधारा जलप्रपात जगदलपुर क्षेत्र में स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक सुरम्य पिकनिक स्थल है।

पोटानार के सुदूर गांव में स्थित, इसमें पहाड़ी से नीचे बहता हुआ पानी का एक आश्चर्यजनक सफेद झरना है।

चित्रधारा झरना घोड़े की नाल के आकार का है, जो इसके प्राकृतिक आकर्षण और सुंदरता को बढ़ाता है।

तेज़ गति से बहता पानी रोमांचक गति से नीचे गिरता है, जिससे यह एड्रेनालाईन-पंपिंग अनुभव चाहने वाले आउटडोर और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है।

चर्रे मार्रे झरने | Charre Marre Waterfalls

चार्रे मार्रे झरने, छत्तीसगढ़ का एक अनोखा आकर्षण, आगंतुकों के लिए एक ताज़ा और अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यह झरना 16 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और काफी ऊंचाई से साफ पानी गिरने का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। जोगीधारा नदी, जो अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए जानी जाती है, इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरने को जन्म देती है, जब यह पहाड़ियों और हरे-भरे पत्तों के बीच से होकर गुजरती है, जिससे सुखद ध्वनि उत्पन्न होती है। झरने के आधार पर, एक जलाशय बनता है, जो ताज़ा पानी में तैरने या डुबकी लगाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है।

घटारानी झरने | Ghatarani Waterfalls

छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घटारानी झरना, रायपुर से 85 किमी दूर स्थित है और एक शानदार प्राकृतिक आकर्षण प्रदान करता है। हरे-भरे हरियाली से घिरा, यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के रूप में कार्य करता है, जो इसे दोस्तों और परिवार के साथ सप्ताहांत बिताने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। घटारानी झरने तक पहुँचने के लिए जंगल के माध्यम से एक छोटी सी यात्रा करनी पड़ती है, जो अनुभव में रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता को जोड़ती है। झरने के तल पर, प्राकृतिक रूप से बना एक पूल है, जहाँ पर्यटक तैरने का आनंद ले सकते हैं, पारिवारिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, या शांत वातावरण में आराम कर सकते हैं।

देव-पहाड़ी झरने | Dev-Pahari Waterfalls

देव पहाड़ी झरने का नाम देव से लिया गया है, जिसका अर्थ है भगवान, और पहाड़ी, जिसका अर्थ है पहाड़, जो पर्वत देवताओं से बहने वाले पानी का प्रतीक है। यह विशाल, दूधिया सफेद झरना परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन की यात्रा के लिए एक आदर्श स्थान है, जो गर्म, धूप वाले मौसम से ताजगी से मुक्ति प्रदान करता है।

झरने से उत्पन्न ठंडी धुंधली हवा इसके आकर्षण को बढ़ाती है, एक ठंडा और तरोताजा करने वाला अनुभव प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित, देव पहाड़ी झरना इस क्षेत्र में हर किसी के लिए एक आकर्षण है, जिसका प्रभावशाली प्रवाह पहाड़ों से गिरता है।

दूध धारा झरने | Dudh Dhara Waterfalls

दूध धारा जलप्रपात को नर्मदा नदी से पानी मिलता है और यह कपिल धारा जलप्रपात से लगभग एक किलोमीटर आगे स्थित है। कपिल धारा से दूध धारा तक पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसमें घने और घने वन क्षेत्रों से होकर गुजरना शामिल है। मानसून के मौसम के दौरान, आगंतुकों को दूध धारा तक पहुंचने के लिए कई धाराओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, जिससे सावधानी को प्राथमिकता मिलती है। दूध धारा जलप्रपात का स्थान जंगल के मध्य में है, इसलिए आगंतुकों को यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

गुल्लू झरने | Gullu Waterfalls

गुल्लू जलप्रपात जशपुर नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर गुलु गांव के पास स्थित है, और परिवार और दोस्तों के साथ विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान है। झरना ईब नदी से निकलता है, जिसका स्रोत बाने, अलोरी, ओर्केला और पाटिया गांवों तक फैला हुआ है, जो गुलु गांव के नजदीक हैं। गुल्लू फॉल्स में एक विशिष्ट सीढ़ी जैसी संरचना है और यह विविध वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है, जो एक शांत वातावरण बनाता है जो शांतिपूर्ण पलायन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

राजपुरी झरना | Rajpuri Waterfalls

राजपुरी झरना छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे आश्चर्यजनक झरनों में से एक है।

यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है जो झरने के आसपास ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा और मछली पकड़ने के अवसर प्रदान करता है, जो इसे एक बहुमुखी गंतव्य बनाता है। यह झरना उराँव आबादी वाले एक आदिवासी गाँव के बीच स्थित है, जिनकी समृद्ध परंपराएँ, रीति-रिवाज और जीवन शैली इस प्राकृतिक आकर्षण के अनूठे आकर्षण में योगदान करते हैं।

अमृत धारा झरने | Amrit Dhara Waterfalls

अमृत धारा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हसदेव नदी पर स्थित

एक प्राकृतिक झरना है। क्षेत्र के अन्य झरनों की तुलना में आकार में छोटा होने के बावजूद, अमृत धारा में एक महत्वपूर्ण गिरावट है, जिसके परिणामस्वरूप एक सुखद धुंध भरा वातावरण है। झरना हरे-भरे हरियाली से घिरा हुआ है, जो आगंतुकों के आनंद के लिए एक मनमोहक और शांत वातावरण बनाता है। अमृत धारा की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम के दौरान होता है जब पानी का प्रवाह सबसे प्रभावशाली होता है। झरने के पास एक महत्वपूर्ण विशेषता भगवान शिव का मंदिर है, जो इस स्थल पर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व जोड़ता है।

मलांझकुडुम झरना | Malanjhkudum Waterfalls

मलांझकुडुम झरना छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, जो दूध नदी पर स्थित है। इस झरने में 9 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर की ऊंचाई वाले तीन झरने हैं, जो एक सीढ़ी जैसी संरचना बनाते हैं। अपनी शानदार सुंदरता के लिए जाना जाने वाला, मलांझकुडुम झरना छत्तीसगढ़ के शीर्ष झरनों में से एक है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के रूप में कार्य करता है। इस झरने की यात्रा का आदर्श समय अक्टूबर और मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है और झरने अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं।

तमरा घूमर झरना | Tamra Ghoomar Waterfalls

चित्रकोट के पास स्थित तमरा घूमर झरना मनमोहक धुंधले सफेद झरनों वाला एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक झरना है। तमरा घूमर फॉल्स की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम के दौरान होता है जब यह अपने सबसे लुभावने समय पर होता है। अपने दूरस्थ स्थान के बावजूद, यह झरना हाल के दिनों में पर्यटकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। तमरा घूमर झरना निर्विवाद रूप से सुंदर है और एक शांत वातावरण प्रदान करता है जो निश्चित रूप से आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देगा।

मंडावा झरने | Mandawa Waterfalls

मंडावा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, जो अपनी सापेक्ष अस्पष्टता के लिए जाना जाता है, जो इसके प्राचीन जल के संरक्षण में योगदान देता है। झरने के आस-पास का क्षेत्र ताज़ा और धुंध भरी हवा प्रदान करता है, जो आगंतुकों के लिए एक ताज़ा अनुभव प्रदान करता है। मंडावा जलप्रपात लगभग 70 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ गिरता है, जिससे चरण-दर-चरण प्रवाह बनता है, और पानी कांगेर नदी में अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक छोटे जलाशय में एकत्र होता है।

बैन झरने | Bane Waterfalls

बैन झरना छत्तीसगढ़ के कुनकुरी से 25 किमी दूर स्थित है, जो एक शांत प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है।

झरना हरे-भरे हरियाली से घिरा हुआ है और एक ताज़ा धुंध भरा वातावरण उत्सर्जित करता है, जो इसे एक आनंददायक गंतव्य बनाता है। बेन फॉल्स पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जो पिकनिक और विश्राम के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। बेन फॉल्स का शांत वातावरण निश्चित रूप से आगंतुकों को शांति और शांति की अनुभूति प्रदान करता है।

हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के झरनों पर यह लेख जानकारी पूर्ण और उपयोगी साबित होगा ।

छत्तीसगढ़ की शिक्षा में एक साहसिक छलांग...

- कोई भी स्कूल अब शिक्षक विहीन नही
- एकल शिक्षकीय स्कूलों में 80 फीसद की गिरावट
- 10,372 स्कूलों का एकीकरण, शिक्षकों का व्यापक युक्ति युक्त करण
- छात्रों को मिलेगी बेहतर शैक्षणिक सुविधा

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और सार्थक पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में यह दूरगामी सुधार, वास्तव में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लंबे समय से चली आ रही शैक्षिक विसंगतियों के समाधान का कारगर प्रयास है।

युक्तियुक्तकरण से पहले, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल की शालाओं में शिक्षकों की कमी, नगरीय इलाकों और उसके समीप की शालाओं में जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की पदस्थपना के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही थी और इसका असर बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा था।

राज्य के लगभग 212 प्राथमिक शालाएं और 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं पूरी तरह से शिक्षक विहीन थीं, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं और 255 पूर्व माध्यमिक शालाएं केवल एक शिक्षक के साथ संचालित हो रही थीं। इसके अतिरिक्त 211 शालाएं ऐसी थीं जहाँ छात्र संख्या शून्य थी, लेकिन शिक्षक पदस्थ थे। इसके अलावा, 166 शालाओं को समायोजित किया गया, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 133 शालाएं शामिल थीं, जिनकी दर्ज संख्या 10 से कम थी और दूरी 1 किमी से कम थी, तथा शहरी क्षेत्रों की 33 शालाएं थीं, जिनकी दर्ज संख्या 30 से कम थी और दूरी 500 मीटर से कम थी।

इन चुनौतियों के बावजूद, छत्तीसगढ़ का छात्र-अध्यापक अनुपात (पीटीआर) राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से बेहतर था, प्राथमिक शालाओं के लिए पीटीआर-20 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 29 है और पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए पीटीआर-18 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 38 है। हालांकि, वितरण असमान था। राज्य में लगभग 17,000 प्राथमिक शालाएं और लगभग 4,479 पूर्व माध्यमिक शालाएं थीं, जिनका पीटीआर-20 से कम था। अकेले शहरी क्षेत्रों में 527 ऐसे विद्यालय थे, जिनका पीटीआर-10 से कम था, जिनमें 15 या उससे अधिक शिक्षकों वाली 08 प्राथमिक शालाएं, 10-15 शिक्षकों वाली 61 शालाएं और 6-9 शिक्षकों वाली 749 प्राथमिक शालाएं थीं, ये आंकड़े बेहतर संसाधन आवंटन की जरूरत को दर्शाते हैं।

इस पहल का मुख्य बिंदु एक ही परिसर में संचालित लगभग 10 हजार 372 शालाओं का एकीकरण था, जिनमें प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल थे। इस विलय से कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें शाला त्यागी छात्रों की संख्या में कमी और छात्रों को बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता का समाप्त होना शामिल है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

प्रदान करने, छोटी कक्षाओं के छात्रों को बड़ी कक्षाओं के छात्रों का सहयोग प्राप्त होने, और कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक समझ और अभिरुचि में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होगा। इस दृष्टिकोण से प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

विद्यालयों के समायोजन के साथ-साथ, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया भी की गई। इस प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर लगभग 13 हजार 793 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। संभाग स्तर पर 863 का और राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। युक्तियुक्तकरण अभियान के प्रारंभिक परिणाम अत्यधिक आशाजनक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा है और कोई भी शिक्षक पद समाप्त नहीं हो रहा है। इसके बजाय ध्यान बेहतर अधोसंरचना वाले विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करने पर है। युक्तियुक्तकरण के पश्चात राज्य में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या शून्य हो गई है। एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में प्रभावशाली 80 प्रतिशत की कमी आई है अब लगभग 1,200 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। एक ही परिसर में स्थित 10,372 विद्यालयों का एकीकरण और 166 ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों का समायोजन पूरा हो चुका है। इससे लगभग 89 प्रतिशत विद्यार्थियों को बार-बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। छात्रों को अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होंगे और विद्यालय की समय सारिणी एवं अन्य गतिविधियों में अधिक एकरूपता रहेगी। इस पहल का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की समझ को बेहतर बनाना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके, छत्तीसगढ़ न केवल वर्तमान कमियों को दूर कर रहा है, बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। जहाँ प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे समग्र विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। युक्तियुक्तकरण का यह कदम एक अधिक कुशल, न्यायसंगत और प्रभावी शैक्षिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

रायपुर नगर निगम द्वारा खाली डायवर्टेड प्लॉट्स पर टैक्स वसूली का निर्णय- राजस्व वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम...

राजधानी रायपुर में नगर निगम ने शहर की आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब नगर निगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में स्थित खाली पड़े डायवर्टेड प्लॉट्स के मालिकों से टैक्स (कर) वसूला जाएगा। यह निर्णय 13 जून को आयोजित राजस्व प्रशिक्षण शिविर में लिया गया, जिसमें महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़ और आयुक्त विश्वदीप की उपस्थिति रही। शिविर के दौरान निगम अधिकारियों ने माना कि वर्तमान समय में निगम की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए नए और वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की तलाश अत्यंत आवश्यक है।

क्यों लिया गया यह फैसला?- बीते कुछ वर्षों में रायपुर नगर निगम की आय अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम का राजस्व 300 करोड़ रुपये से कम था। हालांकि, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनावों के कारण कर जमा करने की अंतिम तिथि अप्रैल तक बढ़ाई गई, जिससे यह आंकड़ा किसी तरह 300 करोड़ के पार पहुंच पाया। अब निगम ने अनुमान लगाया है कि ओपन प्लॉट्स से टैक्स वसूली करके लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए निगम ने रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है।

टैक्स वसूली की रणनीति- नगर निगम ने प्लॉट मालिकों की पहचान के लिए जिला प्रशासन के राजस्व विभाग से सहयोग लेने की योजना बनाई है। इसके तहत-

- शहर के सभी 70 वार्डों में आने वाले पटवारी हलकों का विवरण इकट्ठा किया जाएगा।
- राजस्व रिकॉर्ड, प्लॉट नंबर, और मालिकाना हक की जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखी जाएगी।
- यदि कोई प्लॉट डायवर्टेड है लेकिन उस पर निर्माण नहीं हुआ है, तो वह टैक्स के दायरे में आएगा।

कृषि भूमि पर नियम में लचीलापन- एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि, जो मूलतः कर मुक्त होती थी, अब कर योग्य बन सकती है यदि-

- उस भूमि पर कमरे, हॉल, गोदाम बनाए गए हैं।
- वहाँ व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग की जा रही है।

हालांकि, यदि किसी भूमि पर वास्तविक कृषि कार्य (उपज उत्पादन) हो रहा है, तो वह कर मुक्त रहेगी। इस प्रकार निगम ने कृषि भूमि के दुरुपयोग को रोकने और करदाताओं के बीच न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में स्पष्टता दी है।

संभावित प्रभाव- इस निर्णय से-

- रायपुर नगर निगम की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- शहर के शहरीकरण को अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा।
- फर्जी कृषि भूमि को चिह्नित कर उसका व्यावसायिक उपयोग रोकने में मदद मिलेगी।
- आम नागरिकों को यह संदेश जाएगा कि भूमि को यूं ही खाली रखकर अचल संपत्ति पर कर से बचना अब संभव नहीं।

रायपुर नगर निगम का यह निर्णय राजस्व जुटाने और शहरी नियोजन में पारदर्शिता लाने की दिशा में सराहनीय पहल है। खाली प्लॉट्स पर टैक्स लगाने से न केवल शहरी भूमि का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि इससे बुनियादी सुविधाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। निगम की यह रणनीति अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है।

डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा बस्तर का विकास
केशकाल बाईपास परियोजना एक निर्णायक कदम

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल को लंबे समय से विकास के लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता थी। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, वनवासी जीवनशैली और आधारभूत संरचना की कमी ने यहां की प्रगति को सीमित कर रखा था। परंतु वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास-जिसे डबल इंजन सरकार कहा जा रहा है-से बस्तर अंचल में विकास की गति तीव्र हो रही है। इसका नवीनतम उदाहरण कोंडागांव जिले में 307.96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 11.38 किलोमीटर लंबा केशकाल बाईपास है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

केशकाल बाईपास का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया ह॥-30) के अंतर्गत किया जाएगा, जो केशकाल घाट खंड को पार करता है। यह क्षेत्र लंबे समय से यातायात की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा है — तीव्र मोड़, ढलानें और संकरी सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा इस बाईपास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक की।

यह बाईपास 4-लेन होगा और 'पेव्ड शोल्डर' मानक के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही में भी कोई बाधा नहीं आएगी। इसके निर्माण से न केवल वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, बल्कि यह यात्रा को तेज, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से संतुलित भी बनाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बस्तर अंचल के लिए एक निर्णायक विकासात्मक कदम है, जो न केवल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय समावेशन की दिशा में भी एक ठोस प्रयास है।

श्री साय ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह परियोजना उसी दृष्टिकोण का हिस्सा है।

बस्तर अंचल में कनेक्टिविटी का नया आयाम

केशकाल घाट छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वतीय मार्गों में एक है, जहां भारी बारिश और जाम के कारण यात्रा बेहद कठिन होती है। बाईपास बनने के बाद-

- लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों को शहर के भीतर से नहीं गुजरना होगा।
- घाटी क्षेत्र की जोखिमभरी यात्रा से मुक्ति मिलेगी।

- मालवाहक और आपातकालीन वाहनों की गति और समय की बचत होगी।
- स्थानीय निवासियों को जाम, प्रदूषण और दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी।

बाईपास का यह निर्माण बस्तर अंचल की कनेक्टिविटी को न केवल राज्य के अन्य भागों से जोड़ेगा, बल्कि पड़ोसी राज्यों ओडिशा और आंध्रप्रदेश से भी बेहतर यातायात संपर्क स्थापित करेगा।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

1. व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि

बाईपास से माल परिवहन में लगने वाला समय घटेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में गति आएगी। स्थानीय उत्पाद जैसे कि बस्तर शिल्प, वनोपज, इमली, महुआ और लाख की आसान ढुलाई संभव होगी, जिससे आदिवासी अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।

2. पर्यटन को प्रोत्साहन

बस्तर अपनी नैसर्गिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। बेहतर सड़क संपर्क से कांकेर, केशकाल, जगदलपुर और चित्रकोट जैसे पर्यटक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे घरेलू व विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जो रोजगार और आय के नए साधन उत्पन्न करेगा।

3. शहरीकरण और रोजगार

बाईपास के इर्द-गिर्द शहरी विस्तार और व्यापारिक हब विकसित होने की संभावना है। निर्माण कार्य के दौरान और उसके बाद सड़क रख-रखाव, ढाबा, वाहन मरम्मत केंद्र, होटल आदि के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सुरक्षा और पर्यावरणीय लाभ

1. सड़क दुर्घटनाओं में कमी

केशकाल घाट पर अब तक अनेक दुर्घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनमें से कई जानलेवा रही हैं। नई बाईपास सड़क चौड़ी, समतल और सीधी होगी, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम होगी।

2. प्रदूषण में कमी

शहर के भीतरी हिस्सों में भारी वाहनों का प्रवेश कम होने से ध्वनि और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। यह स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा और पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखेगा।

डबल इंजन सरकार की भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट' नीति अपनाई गई है, जिसमें सड़कों, रेल, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क को प्रमुखता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इस नीति को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। केशकाल बाईपास परियोजना इसी नीति का एक उदाहरण है।

डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर एक ही राजनीतिक दल के शासन में होने से परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति, बजट और क्रियान्वयन मिलता है। बस्तर जैसे पिछड़े और संवेदनशील क्षेत्रों में यह सामंजस्य विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

केशकाल बाईपास परियोजना बस्तर के समग्र विकास की एक कड़ी है। आने वाले वर्षों में निम्नलिखित योजनाएँ भी इससे जुड़ सकती हैं-

- **औद्योगिक गलियारे का विस्तार-** बेहतर सड़क संपर्क से बस्तर औद्योगिक दृष्टि से भी उभर सकता है।
- **फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना-** वनोपज आधारित उद्योगों को बल मिलेगा।

- **डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर-** फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को गांवों तक पहुँचाने की संभावना बढ़ेगी।

केशकाल बाईपास परियोजना न केवल एक सड़क निर्माण की योजना है, बल्कि यह बस्तर अंचल को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक पहल है। यह परियोजना जनजातीय क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाएगी, कनेक्टिविटी को सुधारकर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी, और स्थानीय लोगों को रोज़गार व सुविधा दोनों प्रदान करेगी।

डबल इंजन सरकार के तहत इस प्रकार के योजनाबद्ध और दूरदर्शी निर्णय ही बस्तर को विकास के नए पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की यह पहल छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण है।

गर्मियों की हेल्दी सब्ज़ी- तोरई के जबरदस्त फायदे जो आप नहीं जानते होंगे..

गर्मियों में जब पेट को कुछ हल्का और सादा चाहिए, तब भारतीय रसोई में एक सब्जी बार-बार बनती है - तोरई (या तुरई)। भले ही इसका स्वाद कुछ लोगों को फीका या बेमज़ा लगे, लेकिन जब बात सेहत की आती है, तो यह सब्जी किसी सुपरफूड से कम नहीं। गर्मियों की यह सादी सी सब्जी आपके शरीर को ठंडक भी देती है और कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करती है। अगर आप तोरई को सिर्फ एक दाल के साथ खाने वाली सामान्य सब्ज़ी समझते हैं, तो इस लेख को पढ़ने के बाद आप इसे अपनी थाली में रोज़ शामिल करना शुरू कर देंगे।

राखी श्रीवास्तव

तोरई क्यों है खास...?

तोरई हल्की, जल्दी पचने वाली और पानी से भरपूर सब्जी है। गर्मी के मौसम में यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने और पाचन को सुधारने में अहम भूमिका निभाती है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं - जैसे-

- विटामिन A, B और C
- फाइबर
- मैग्नीशियम और आयरन
- 80% से अधिक पानी

वैज्ञानिक भी मानते हैं तोरई के फायदे

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और भारतीय आयुर्वेद ग्रंथों में तोरई के औषधीय गुणों का ज़िक्र है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि तोरई में 50 से ज़्यादा जैविक रसायन पाए जाते हैं, जैसे-

- **फ्लावोनॉयड्स**- शरीर में सूजन और एलर्जी को कम करते हैं।
- **एंथ्राक्विनोन्स** - पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं।
- **सैपोनिन और ट्राइटरपीन**- बैक्टीरिया व वायरस से बचाव करते हैं।
- **प्रोटीन और फैटी एसिड्स**- शरीर की ताकत बढ़ाते हैं और थकान कम करते हैं।

डायबिटीज के लिए रामबाण

तोरई खासतौर पर मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक पेप्टाइड्स शरीर में इंसुलिन की तरह काम करते हैं, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है।

कैसे करें सेवन- उबली हुई तोरई को हल्दी और जीरे से बनाकर दाल के साथ खाएं।

- बिना ज्यादा मसालों के, भाप में पकी तोरई डायबिटीज में और ज्यादा फायदेमंद होती है।

बालों और त्वचा के लिए वरदान- तोरई सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर से भी उपयोगी है। यह आपके बालों को झड़ने और सफेद होने से बचा सकती है, साथ ही त्वचा की समस्याओं में राहत देती है।

घरेलू नुस्खे

- **मस्से या दाद पर**- तोरई का रस लगाने से सूजन कम होती है।
- **फोड़े पर**- इसकी जड़ को ठंडे पानी में घिसकर लगाने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है।
- **चकत्तों पर**- बेल को मक्खन में घिसकर लगाने से खुजली और जलन में राहत मिलती है।

पाचन और लिवर के लिए अमृत

तोरई फाइबर से भरपूर होती है, जिससे कब्ज, गैस और बवासीर जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। इसके अलावा यह लिवर की सफाई (डिटॉक्स) करती है और खून को शुद्ध करती है।

विशेष नुस्खा- कड़वी तोरई और बैंगन का सेवन

आयुर्वेद में एक खास नुस्खा बताया गया है- कड़वी तोरई और बैंगन को मिलाकर हल्के मसालों के साथ पकाएं और इसका सेवन करें। यह बवासीर के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है।

और भी फायदे

लाभ	विवरण
शरीर को ठंडक	गर्मियों में तापमान नियंत्रण में रखती है
डिहाइड्रेशन से बचाव	शरीर को हाइड्रेटेड रखती है
मानसिक शांति	शरीर को हल्का महसूस कराती है, जिससे मूड बेहतर होता है
खून की सफाई	टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और रक्तचाप नियंत्रित करती है

कैसे करें तोरई को स्वादिष्ट..?

तोरई को कई तरीके से बनाया जा सकता है ताकि यह स्वादिष्ट भी लगे और स्वास्थ्यवर्धक भी रहे

- **तोरई-चना दाल-** हल्के मसालों के साथ, प्रोटीन युक्त रेसिपी।
- **तोरई की सूखी सब्जी-** प्याज और हल्दी के साथ, रोटी के साथ परोसे।
- **तोरई-टमाटर करी-** टमाटर और थोड़े धनिया पत्ते डालकर स्वाद बढ़ाएं।
- **तोरई का सूप-** उबालकर ब्लेंड करें, थोड़ा नमक और काली मिर्च डालें - बेहतरीन डिटॉक्स सूप!

हर थाली में तोरई क्यों ज़रूरी?

तोरई दिखने में भले ही आकर्षक न हो, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ इतने व्यापक हैं कि इसे रोज़ के भोजन में शामिल करना समझदारी होगी। खासकर गर्मियों के मौसम में, जब शरीर को ठंडक, ऊर्जा और हल्का भोजन चाहिए - तोरई एक आदर्श विकल्प बन जाती है।

(अब जब आप इसके गुणों को जान चुके हैं, तो अगली बार तोरई को सिर्फ एक साधारण सब्ज़ी न समझें, बल्कि एक औषधीय आहार मानें ङ्क जो आपके शरीर को भीतर से स्वस्थ रखता है)

स्वादिष्ट आइसक्रीम घर पर कैसे बनाए...

जी व्ही एस रुक्मणि देवी

गर्मी के मौसम में ठंडी और स्वादिष्ट चाकलेट आइसक्रीम का आनंद लेले का मन किसे नहीं करना ? घर पर बनी चाकलेट आइसक्रीम का स्वाद तो बाजार की आइसक्रीम से कहीं ज्यादा मजे दार होता है. तो चलिए ,आज हम आपको घर पर आसानी से चाकलेट आइसक्रीम बनाने की एक मजेदार रेसिपी बताते हैं.

सामाग्री

2 कप फुल क्रीम दूध
1 कप ताजी हेवी क्रीम
1/2 कप चीनी या स्वादानुसार
1/4 कप अन स्वीटेड कोको पाउडर
1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस
चुटकी भर नमक (वैकल्पिक ,स्वाद बढाने के लिए)
गार्नीशिंग के लिए चाकलेट चिप्स या कटे हुवे नट्स

बनाने का तरीका -

सुखी सामाग्री मिलाएं - एक माध्यम आकार के बर्तन में चीनी ,कोको पाउडर और नमक (यदि इस्तेमाल कर रहें हैं) डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि कोई गुठली न रहें.

दूध मिलाये- धीरे धीरे थोडा थोडा दूध डालते हुए सूखी सामाग्री के साथ मिलाये 7 लगातार चलाते रहें ताकि एक चिकना घोल बन जाए.

पकाएं- इस मिश्रण को माध्यम आंच पर रखें और लगातार चलाते रहें. उबाल आने तक पकाएं. उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और 2-3 मिनट तक और पकाए , जब तक की मिश्रण थोडा गाढ़ा न हो जाए. ध्यान रखें की यह बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए.

ठंडा करें- आंच बंद कर दें और मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने दें. आप इसे जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रीज़ में भी रख सकतें हैं.

क्रीम मिलाएं- जब मिश्रण पूरी तरह से ठंडी हो जाए , तो इसमें ताज़ी क्रीम और वनील एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

फ्रीज़ करें (पहला चरण)- मिश्रण को एक एयर टाईट कंटेनर में डाले और कम से कम 4-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखे , जब तक की यह किनारों से जमना शुरू न हो जाए.

ब्लेंड करें (जरूरी चरण)- कंटेनर को फ्रीज़र से निकाले और मिश्रण को ब्लेंडर या हेंड ब्लेंडर की मकदाद से ब्लेंड करें , ताकि यह एकदम चिकना और क्रीमी हो जाए. यह चरण आइसक्रीम को क्रिस्टली होने से बचाता है और उसे स्मूथ टेक्सचर देता है. यदि आपके पास ब्लेंडर नहीं है , तो आप इसे कांटे या व्हिस्क से भी अच्छी तरह से फेंट सकते हैं.

फ्रीज़ करें (दूसरा चरण)- ब्लेंड किये हुवे मिश्रण को वापस एयर टाईट कंटेनर में डाले और कम से कम 6-8 घंटे या रात भर के लिए फ्रीजर में जमने दें.

परोसें- आपकी स्वादिष्ट होममेड चाकलेट आइसक्रीम तैयार है. इसे स्कूप की मदद से निकाले और चाकलेट चिप्स या काले हुवे नट्स से गार्नीशिंग करके ठंडा परोसें.

सुझाव-
- बेहतर स्वाद के लिए बेहतरीन कोको पाउडर इस्तेमाल करें.
- आप अपनी पसंद के अनुसार चीनी की मात्रा को समायोजित कर सकते हैं.
- अधिक रिच और क्रीमी आइसक्रीम के लिए फुल फैट दूध और क्रीम का इस्तेमाल करें.
- आप इस बेसिक रेसिपी में अपनी पसंद के अनुसार चाकलेट के टुकड़े , कॉफ़ी पाउडर या अन्य फ्लेवर भी मिला सकते हैं.
- आइसक्रीम को सर्व करने से 10-15 पहले फ्रीज से निकाल लें ताकि यह थोडा नरम हो जाए और स्कूप करने में आसानी हो
- इस प्रकार इस गर्मी में घर पर बनी इस स्वादिष्ट चाकलेट आइसक्रीम का आनंद लें और गर्मी को ठंडा करां.

रायपुर एक बार फिर बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का गवाह भारत-न्यूजीलैंड टी 20 मुकाबला 23 जनवरी 2026 को...

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रंग में रंगने को तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी 2026 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में अपनी 28वीं एपेक्स काउंसिल की बैठक के बाद दी। यह चौथी बार होगा जब रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा, और इस बार दर्शकों को टी-20 फॉर्मेट का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा। इससे पहले 2023 में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला खेला गया था, तब कम स्कोरिंग के कारण दर्शकों को अपेक्षित आनंद नहीं मिल पाया था। लेकिन अब टी-20 मैच की घोषणा ने खेल प्रेमियों में एक बार फिर से उत्साह भर दिया है।

BCCI का फैसला और बैठक की प्रमुख बातें

28वीं एपेक्स काउंसिल की बैठक में BCCI के शीर्ष पदाधिकारियों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड दौरे का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में क्चष्टष्ठ के चेयरपर्सन देवजीत साइकिया, कोषाध्यक्ष प्रभतेज भाटिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला शामिल थे। बैठक के बाद क्चष्टष्ठ ने आधिकारिक वेबसाइट पर सीरीज के कार्यक्रम और वेन्यू की घोषणा की।

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज- रायपुर को मिला दूसरा मुकाबला

2026 की शुरुआत क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज के तहत रायपुर को दूसरा मुकाबला मेजबानी के लिए मिला है। यह मैच 23 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन रायपुर के नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो कि देश के सबसे बड़े और सुंदर स्टेडियमों में से एक माना जाता है।

रायपुर स्टेडियम- गौरवशाली मेजबानी का इतिहास

रायपुर का यह स्टेडियम अब तक कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन कर चुका है। 2023 में भारत-न्यूजीलैंड के बीच एकदिवसीय मुकाबला यहीं खेला गया था। हालांकि वह मुकाबला कम स्कोरिंग रहा था, लेकिन इस बार T20 मुकाबले से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। इसके अतिरिक्त IPL और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी भी रायपुर ने सफलतापूर्वक की है।

स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 65,000 है और इसकी आधुनिक सुविधाएं इसे देश के अग्रणी स्टेडियमों की सूची में शामिल करती हैं। यहां की पिच आमतौर पर बैलेंस्ड रहती है, जिससे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मौका मिलता है।

2025 में भी रायपुर बनेगा इंटरनेशनल मैच का हिस्सा

रायपुर को केवल 2026 ही नहीं, बल्कि 2025 में भी एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। BCCI के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के तहत दूसरा मुकाबला रायपुर में ही आयोजित होगा। यह मैच 3 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। यानी लगातार दो महीनों में रायपुर को दो बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा।

राज्य सरकार और BCCI का साझा प्रयास

छत्तीसगढ़ सरकार और BCCI के सहयोग से यह आयोजन रायपुर के खेल पर्यटन को और मजबूती देगा। मुख्यमंत्री कार्यालय और खेल विभाग की लगातार कोशिशों का नतीजा है कि राज्य की राजधानी अब क्रिकेट के नक्शे पर मजबूती से अपनी पहचान बना चुकी है। BCCI के इस फैसले से न केवल खेल प्रेमियों को रोमांच मिलेगा, बल्कि यह आयोजन राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

खेलप्रेमियों में उत्साह का माहौल

मैच की घोषणा के बाद से ही रायपुर समेत पूरे राज्य के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। टिकट बुकिंग, होटलों की तैयारी और स्थानीय आयोजन समितियों की सक्रियता से यह तय है कि यह आयोजन भव्य और सफल होगा। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की तैयारियां भी प्रशासन ने शुरू कर दी हैं।

T20 मैच से मिलेगी नई ऊर्जा

T20 फॉर्मेट तेज गति वाला और रोमांचक होता है, जिसमें चौके-छक्कों की बरसात होती है। खासकर जब टीमें भारत और न्यूजीलैंड जैसी हों, तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। दोनों ही टीमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी-20 टीमें मानी जाती हैं और उनके पास युवा व अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन है। ऐसे में 23 जनवरी 2026 को रायपुर में होने वाला मुकाबला न सिर्फ खेल का रोमांच देगा, बल्कि राज्य के युवाओं को प्रेरित भी करेगा।

भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक उत्सव है। रायपुर को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी मिलना राज्य के लिए गर्व की बात है। यह न केवल खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन के लिहाज से भी अत्यंत लाभकारी है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों को भी ऐसे आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिले, यह राज्य सरकार और BCCI की साझा जिम्मेदारी बनती है।

23 जनवरी 2026 को जब भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगे, तब रायपुर का आसमान क्रिकेट के शोर से गूंजेगा और एक बार फिर खेल प्रेमियों को मिलेगा एक यादगार अनुभव।

हाउसफुल 5 का नहीं चल पा रहा जादू, कलेक्शन में आई गिरावट

अगर फिल्म हाउसफुल 5 के अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 31 करोड़ रूपये, तीसरे दिन 32.5 करोड़ रूपये, चौथे दिन 13 करोड़ रूपये, वहीं पांचवें दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट नजर आई.

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 बीते दिनों सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जब से फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के सामने आया था, अक्षय कुमार के फैंस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्सक थे. फिल्म को काफी शानदार ओपनिंग मिली थी, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम होता जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि अभी तक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा.

फिल्म का कलेक्शन

अगर फिल्म हाउसफुल 5 के अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 31 करोड़ रूपये, तीसरे दिन 32.5 करोड़ रूपये, चौथे दिन 13 करोड़ रूपये, वहीं पांचवें दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट नजर आई. फिल्म ने 10.75 करोड़ रूपये के आसपास का कलेक्शन किया है. इस तरीके से फिल्म का अभी तक कुल मिलाकर 111.25 करोड़ रूपये का कलेक्शन हो चुका है. क्योंकि इस फिल्म में काफी लंबी चौड़ी कास्ट है. अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ऑडियंस के फिल्म को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. फिल्म में दो क्लाइमैक्स भी दिखाई गए हैं.

फिल्म की कास्ट

अगर इस फिल्म की पूरी कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, चंकी पांडे, जैकलिन फर्नांडीज, चित्रांगदा सिंह, नरगिस फाखरी, जॉनी लीवर, नाना पाटेकर, सोनम बाजवा, जैसे तमाम एक्टर्स नजर आए हैं. अब फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक पहुंचता है, इसके लिए आपको थोड़े दिनों तक का और इंतजार करना होगा. एक्टर अक्षय कुमार को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. क्योंकि उनकी पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं देखा पाई हैं. अगर यह फिल्म सक्सेसफुल होती है तो यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर में चार चांद लगा सकती है. इसके अलावा अक्षय कुमार जल्द ही और अन्य फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं.

IPL 2025 Final: 18 साल बाद RCB बनी IPL चैंपियन

आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांच और भावनाओं से भरा पर्व बन गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 17 वर्षों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम की। पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में आरसीबी ने 6 रनों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। यह जीत न केवल टीम के खिलाड़ियों बल्कि उनके करोड़ों फैन्स के लिए भावुक क्षण बन गई, जो वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

एक सपने की शुरुआत- फाइनल में चौथी बार पहुंची RCB

आरसीबी इससे पहले 2009, 2011 और 2016 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन हर बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। टीम पर चोकर्स का टैग लग गया था, और आलोचनाएं उनके प्रदर्शन के पीछे की छाया बनी रहीं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और थी– कप्तान फाफ डु प्लेसिस की रणनीति, विराट कोहली का अनुभव, और गेंदबाजों की सटीकता ने टीम को विजयी बना दिया।

टॉस और पहली पारी- आरसीबी की चुनौतीपूर्ण शुरुआत

मैच का टॉस पंजाब किंग्स ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो शुरुआती तौर पर सही साबित होता दिखा। आरसीबी की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन बड़े स्कोर की उम्मीदों को अंत में पंजाब के गेंदबाजों ने झटका दिया। टीम 20 ओवरों में 190 रन ही बना सकी।

विराट कोहली ने 43 रन बनाए, लेकिन यह पारी अपेक्षाकृत धीमी रही–35 गेंदों में सिर्फ 3 चौके और 18 डॉट गेंदें। फिल साल्ट (16), मयंक अग्रवाल (24), रजत पाटीदार (26), लियाम लिविंगस्टन (25) और जितेश शर्मा (24) ने छोटी लेकिन काम की पारियां खेलीं। टीम के मध्यक्रम ने थोड़ी निराशा की, और अगर अंतिम ओवरों में पंजाब के गेंदबाज इतने घातक न होते, तो स्कोर 210 तक जा सकता था।

पंजाब की गेंदबाजी- अर्शदीप और जैमीसन की आग उगलती गेंदें

पंजाब की ओर से काइल जैमीसन और अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। दोनों ने तीन–तीन विकेट लेकर आरसीबी की बल्लेबाजी को दबाव में डाला। विशेष तौर पर अर्शदीप ने अंतिम ओवर में केवल तीन रन दिए और तीन विकेट लिए, जिससे बेंगलुरु 200 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। उनका यह ओवर मैच के निर्णायक पलों में से एक बन गया।

लक्ष्य का पीछा- पंजाब की तेज शुरुआत, लेकिन स्थिरता की कमी

191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स ने आक्रामक

शुरुआत की। पहले विकेट के लिए प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने 43 रन जोड़े। लेकिन इसके बाद जोश हेजलवुड ने प्रियांश को 24 रन पर आउट कर दिया, जिससे पंजाब की पारी में पहला ब्रेक लगा।

इसके बाद प्रभसिमरन (29), जोश इंगलिस (39), और कप्तान श्रेयस अय्यर (1) जल्द ही पवेलियन लौट गए। टीम की बल्लेबाजी क्रम में निरंतरता का अभाव दिखा, और कोई भी बल्लेबाज ऐसी पारी नहीं खेल सका जो लक्ष्य के करीब पहुंचा सके।

क्रुणाल पांड्या- गेंदबाजी का मास्टरक्लास

मैच का असली टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ क्रुणाल पांड्या का स्पेल। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर दो बेहद महत्वपूर्ण विकेट लिए — पहले सेट बल्लेबाज जोश इंगलिस को आउट किया और फिर 17वें ओवर में दो और विकेट लेकर पंजाब की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। उनकी गेंदबाजी ने पंजाब की रन गति को थामने के साथ ही टीम को मानसिक दबाव में ला दिया।

अंतिम ओवर का रोमांच- दिल थाम देने वाला समापन

जब आखिरी ओवर शुरू हुआ, पंजाब को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे। लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों — शेफर्ड, भुवनेश्वर और क्रुणाल ने एकजुट होकर टीम को संभाला। पंजाब सिर्फ 6 रन बना सकी और 7 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच हार गई।

विराट कोहली की भावुक जीत

यह मैच सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, बल्कि एक सपने के पूरे होने की कहानी थी– विशेषकर विराट कोहली के लिए, जो 2008 से आरसीबी का हिस्सा रहे हैं। जब मैच खत्म हुआ और जीत तय हुई, कोहली मैदान पर ही बैठकर रो पड़े। यह दृश्य न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम कर गया। कोहली की यह जीत उनके करियर की सबसे भावुक उपलब्धियों में से एक बन गई।

बेंच स्ट्रेंथ और सामूहिक प्रयास की जीत

आरसीबी की यह जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं थी, बल्कि पूरी टीम के संतुलित प्रदर्शन का नतीजा थी। जहां बल्लेबाजी में हर खिलाड़ी ने थोड़ा-थोड़ा योगदान दिया, वहीं गेंदबाजी में क्रुणाल, हेजलवुड, और शेफर्ड ने कमाल दिखाया। फील्डिंग में भी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, कई अहम कैच और रनआउट ने पंजाब की कोशिशों को कमजोर कर दिया।

कोचिंग स्टाफ और रणनीति की भूमिका

इस बार आरसीबी के कोचिंग स्टाफ ने भी शानदार भूमिका निभाई। सही खिलाड़ियों का चयन, विपक्ष की कमजोरी के अनुसार रणनीति बनाना और खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करना - इन सबने मिलकर टीम को मजबूत बना दिया। कप्तान फाफ डु प्लेसिस और कोच संजय बांगड़ की जोड़ी ने टीम में अनुशासन और एकता की भावना भर दी।

आईपीएल 2025- एक अविस्मरणीय सीजन

आईपीएल 2025 का यह संस्करण शुरुआत से ही रोमांचक रहा। कई टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, युवा खिलाड़ियों ने खुद को साबित किया और पुराने दिग्गजों ने अनुभव के दम पर टीमों को संभाला। लेकिन अंत में आरसीबी ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपने नाम इतिहास लिखवा दिया।

फैन्स की दीवानगी- 17 साल बाद खुला जश्न का दरवाजा

आरसीबी की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल छा गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #RCBChampion2025 ट्रेंड करने लगा। बेंगलुरु शहर की सड़कों पर जश्न, ढोल-नगाड़े, और आतिशबाजी के साथ फैंस ने 17 साल के इंतजार को जश्न में बदल दिया।

अब चोकर्स नहीं, चैंपियन है RCB

आईपीएल 2025 का फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, यह भावना, संघर्ष और जुनून की जीत थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह साबित कर दिया कि निरंतरता, विश्वास और टीमवर्क के दम पर कितनी भी लंबी प्रतीक्षा को जीत में बदला जा सकता है। अब वे चोकर्स नहीं, बल्कि गर्व के साथ चैंपियंस कहलाते हैं।

SHRI BALAJI VIDYA MANDIR
ANDHRA ASSOCIATION RAIPUR
सा विद्या या विमुक्तये
Shri Balaji Vidya Mandir
Managed by
ANDHRA ASSOCIATION, RAIPUR
46
YEARS OF EXCELLENCE
Admissions
OPEN
2025-26
FOR NURSERY TO CLASS XII
The School of Quality
Education and Temple of Wisdom
Your kids Deserve
The best Education
Take Pride to
Admit your child in
one of the best schools
with
Quality Education
Branch Office
Contact Office Between
10:00 AM & 03.00 PM
Sec-II Devendra Nagar Raipur (C.G.)
Emaill: shribalajischoolraipur@gmail.com
Website : sbvmraipur.com
Shri Balaji Vidya Mandir
Managed by ANDHRA ASSOCIATION, RAIPUR
Basant Vihar Gate No.1 Near Basant Vihar
Garden, Gondwara Raipur (C.G.)
Time -10:00 AM & 03.00 PM
SBVM Kids Zone
Managed by ANDHRA ASSOCIATION, RAIPUR
Vijay Nagar, Behind Patel Cable, Bhanpur, Raipur
Time -10:00 AM & 01.00 PM
MOB: 9406400007, 9329128867

छत्तीसगढ़ संवाद आर.ओ.-13302/236

छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के नए अवसर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

"अब उद्यमी बनने की राह हुई आसान"

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0

- **पोर्टल के माध्यम** से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा
- **उद्योगों की स्थापना** में सहयोग, युवाओं को रोजगार के मौके
- **ऑफलाइन मोड में** किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं
- पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का **क्लीयरेंस**
- **ई-चालान** के माध्यम से पेमेंट की सुविधा
- **सिंगल क्लिक पर** देखी जा सकती है आवेदन की स्थिति

QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in